घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 176- मंगलवार 28 - अप्रैल 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा...
वडोदरा के एक ही परिवार के चार लोगों की हुई मौत

पंचमहल,27 अप्रैल 2026। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पंचमहल जिले के कालोल के पास सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से जा रही कार पर चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार पांच लोगों में से चार की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि एक व्यक्ति सुरक्षित बच गया। जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुए सभी लोग वडोदरा के रहने वाले थे। खींजी परिवार के सभी सदस्य राजस्थान से वापस लौट रहे थे,तभी कालोल के पास यह हादसा हो गया। मृतकों में साजिद इकबाल खींजी (55 वर्ष),इलियास इकबाल खींजी (50 वर्ष),इशाक इकबाल खींजी (48 वर्ष) और रेहान अजगर खींजी (35 वर्ष) के रूप में हुई है। एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से वडोदरा में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार में फंसे मृतकों को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए कालोल की रेफरल अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल, इस मामले में पंचमहल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार के डिवाइडर पार करने के कारणों और हादसे के समय वाहन की गति की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि चालक के नियंत्रण खोने के कारण यह दुर्घटना हुई।

टीएमसी सांसद मिताली की कार पर ईंट-पत्थर से हमला...सांसद,उनका ड्राइवर घायल,3 भाजपा कार्यकर्ता अरेस्ट

कोलकाता,27 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल के हुगली में सोमवार को टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। हमला उस वक्त हुआ, जब मिताली बाग गोगहाट से आरामबाग में अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने जा रही थीं। हमले में कार के शीशे टूट गए। सांसद और उनके ड्राइवर को चोट आई है। दोनों को आरामबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद कैमरे के सामने मिताली बाग फूट-फूटकर रो पड़ीं। उन्होंने कहा, 'मेरी गाड़ी की हालत देखिए। उन लोगों ने बड़े-बड़े पत्थर फेंके। मैं किसी तरह जान बचाकर निकली हूं।' टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने गोगहाट में सांसद की गाड़ी पर ईंट-पत्थर और लाठियों से हमला किया। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- गृह मंत्री अमित शाह ने धमकी दी थी कि जो भी घर से बाहर निकलेगा, उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। उसी के बाद यह हमला हुआ। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सिंतु संत्रा, सनातन संत्रा और राजकुमार रॉय के रूप में की गई है। दावा है कि तीनों भाजपा कार्यकर्ता हैं।

महिला वकील पर जानलेवा हमले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान,कई महत्वपूर्ण आदेश दिए

नई दिल्ली,27 अप्रैल 2026। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकील मधु राजपूत पर उनके पति द्वारा जानलेवा हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर घटना का स्वतः संज्ञान लिया और तुरंत सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। आरोप है कि 24 अप्रैल की रात को पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला वकील पर तलवार जैसी धारदार हथियार से हमला किया। हमले में उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद उन्हें उनके सोनिया विहार स्थित ऑफिस में बंद कर दिया गया, जिससे इलाज में देरी हुई। तीन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया। केवल प्राथमिक उपचार के बाद सुबह करीब 6 बजे उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती किया जा सका। पीड़िता की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर गहरी चिंता जताई। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करना बेहद चिंताजनक है।

बैरकपुर की धरती से बंगाल में परिवर्तन होगा,4 मई के बाद रोजगार से जुड़े पांच बड़े कदमों की घोषणा
अब मुझे भाजपा के शपथ ग्रहण में आना है : पीएम मोदी

बैरकपुर,27 अप्रैल 2026। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बैरकपुर की ऐतिहासिक धरती जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी थी, अब बंगाल में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को सबोधित करते हुए राज्य में बड़े बदलाव का दावा किया। उन्होंने कहा,'बंगाल की सेवा करना, उसे सुरक्षित करना और बड़ी चुनौतियों से बचाना मेरे लिए भाग्य भी है और दायित्व भी और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा।' उन्होंने रैली को इस चुनाव की अपनी अंतिम सभा बताते हुए कहा कि वे पूरे विश्वास के साथ लौट रहे हैं कि 4 मई के बाद उन्हें भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फिर आना होगा। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य में रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही हैं, जबकि गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल-फूल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में करीब एक दर्जन जूट मिलें बंद हुई हैं। उन्होंने कहा,'एक ओर रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही हैं,दूसरी ओर बम फैक्ट्रियां और तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट का विस्तार हो रहा है,यही तृणमूल का महाजंगल राज है।'उन्होंने कहा कि तृणमूल की राजनीति केवल गाली, धमकी और झूठ फैलाने तक सीमित रह गई है और उसके नेताओं ने अपने 15 वर्षों के शासन का कोई हिसाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल ने 'मां, माटी, मानुष' के अपने ही नारे को भुला दिया है और महिलाओं, किसानों तथा युवाओं के लिए कुछ नहीं किया।

कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा

4 मई के बाद रोजगार से जुड़े पांच बड़े कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से समय पर होंगी, खाली पद भरे जाएंगे और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा, गांवों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी और शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कोलकाता को लेकर भी तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर को लंदन बनाने का वादा किया गया था, लेकिन 15 वर्षों में उसकी पहचान बदल दी गई और घुसपैठियों को बसाया गया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे कोलकाता की पहचान को बचाने के लिए एकजुट हों। प्रधानमंत्री ने 'अंग, बंग और कलिंग' का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार और ओडिशा में भाजपा को समर्थन मिल चुका है और अब बंगाल की बारी है। उन्होंने 'वंदे मातरम्' को 21वीं सदी में बंगाल के नव-निर्माण का मंत्र बताते हुए राज्य के विकास को विकसित भारत के लक्ष्य के लिए आवश्यक बताया।

पीएम मोदी बोले...बंगाल बदलाव की ओर बढ़ रहा है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति,संस्कृति और आजादी में बंगाल के बेटों-बेटियों की बड़ी भूमिका रही है। यहां पास ही ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का घर है। जिन्होंने 'वंदे मातरम की रचना की थी। यह एक अद्भुत संयोग है कि 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे हो रहे हैं और बंगाल एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बंगाल भाजपा सरकार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 21 हजार रुपए की मदद देगी। बेटियों को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण मिलेगा। मोदी ने गरीब परिवार की बहन और बेटियों के लिए मुफ्त इलाज और अनाज की सुविधा दी है। भाजपा की पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की बेंच की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे : केजरीवाल

नई दिल्ली,27 अप्रैल 2026। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में चल रहे अपने केस की कार्यवाही में न तो स्वयं पेश होंगे और न ही उनकी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने 'हितों के टकराव' के कारण यह निर्णय लिया है। उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि सिद्धांतों से है। उनके मुताबिक न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। महात्मा गांधी के 'सत्याग्रह' का संदर्भ देते हुए केजरीवाल ने कहा कि यदि अंतरात्मा की आवाज कहती है कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ चुप न रहो उसका सामना करो लेकिन उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय न मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, फिर शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। बाद में उसके जो भी परिणाम हों वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफ़रत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ न्यायमूर्ति स्वर्णकांता के सामने अपनी बात रखी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार थमा,29 अप्रैल को मतदान

नई दिल्ली/कोलकाता,27 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार सोमवार शाम थम गया।राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा की बाकी 142 सीटों पर बुधवार (29 अप्रैल) को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रथम चरण के 23 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान कई मतदान केंद्रों पर हिंसा को देखते हुए इस बार सुरक्षा के और कड़े प्रबंध किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में कोलकाता,हावड़ा,नादिया,उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान की सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में लगभग 40 हजार मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में कई संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कुल 2,348 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इनमें सबसे अधिक 507 कंपनियां उत्तर 24 परगना जिले में तैनात होंगी। बांग्लादेश से सटी लंबी तटीय सीमा और सुंदरबन क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में तटीय गश्त और सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने सीमा क्षेत्रों में विशेष चौकसी और सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दो बड़े रोड शो किए। पहला बेहाला थाना से मंटन तक और दूसरा हुगली के चंदननगर बागबाजार क्षेत्र में आयोजित किया गया। रोड शो के दौरान अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जादवपुर और टॉलीगंज के प्रत्याशियों के समर्थन में जादवपुर के सुकांत सेतु से जनसभा मार्च में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भी जनसभा की। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राणाघाट,हुगली,आरामबाग और महेशतला में व्यापक प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चार चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने उत्तर 24 परगना के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो से शुरुआत की, इसके बाद हुगली के धानेखाली में जनसभा को संबोधित किया। फिर कोलकाता के दमदम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और अंत में राजारहाट गोपालपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

ममता बनर्जी ने किया जीत का दावा...बोलीं- मां माटी मानुष की लहर,अब सिर्फ वक्त का इंतजार

नई दिल्ली,27 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मां, माटी, मानुष की जीत अब भविष्यवाणी नहीं, बल्कि सिर्फ समय की बात है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित पदयात्राओं और जनसभाओं में आम लोगों का जबरदस्त उत्साह, स्नेह और भावनात्मक समर्थन देखकर वह बेहद प्रभावित हुई हैं। उन्होंने लिखा कि यह रिश्ता वर्षों से हर चुनौती के समय जनता के साथ खड़े रहने से बना है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सदियों से सौहार्द, संस्कृति और सभ्यतागत गौरव का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र धरती पर उन विभाजनकारी और विनाशकारी ताकतों के लिए जगह नहीं , जो बंगाल को उसके अधिकारों से वंचित रखना चाहती हैं। ऐसी ताकतें बंगाल की विरासत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता की लालसा में जनता के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को बंगाल की जागरूक और एकजुट जनता लोकतांत्रिक जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार के विकास कार्य राज्य के हर कोने तक पहुंचे हैं और कोई भी दुर्भावनापूर्ण ताकत इस रफ्तार को रोक नहीं सकती।

पश्चिम बंगाल में चुनावी जब्ती 510 करोड़ पार,पिछले चुनाव से 339 करोड़ अधिक

नई दिल्ली,27 अप्रैल 2026। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान अब तक अवैध नकदी,शराब, ड्रग्स,कीमती धातु और अन्य वस्तुओं को मिलाकर कुल मूल्य 510 करोड़ रुपये से अधिक की चीजें जब्त की हैं। यह आंकड़ा 2021 के विधानसभा चुनावों में दर्ज 339 करोड़ रुपये की जब्ती से भी अधिक है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक पश्चिम बंगाल में 2,728 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों और 3,142 निगरानी टीमों को तैनात किया गया है। ये टीमें शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई करती हैं और विभिन्न स्थानों पर अचानक नाके लगाकर जांच करती हैं। इसके अलावा अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और वितरण के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 27 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में 30 करोड़ रुपये नकद,48 लाख लीटर से अधिक शराब जिसकी कीमत 126.85 करोड़ रुपये है, 110.12 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स, 58.28 करोड़ रुपये कीमती धातु और 184.85 करोड़ रुपये मूल्य के अन्य सामान जब्त किए गए।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर,100 प्रतिशत भारतीय निर्यात टैक्स-फ्री

नई दिल्ली,27 अप्रैल 2026। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में सोमवार को एक नए युग की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यापार, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाला है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष टॉड मैक्ले की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण समझौते को आधिकारिक रूप दिया गया। यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत मानी जा रही है।

रिकॉर्ड समय में समझौता और निर्यातकों को संजीवनी

इस एफटीए की सबसे खास बात इसकी गति रही है। 16 मार्च, 2025 को शुरू हुई बातचीत को रिकॉर्ड नौ महीनों के भीतर संपन्न कर लिया गया। इस समझौते के लागू होने से भारत को सभी टैरिफ उत्पादों पर तत्काल 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। इसके परिणामस्वरूप,न्यूजीलैंड को होने वाले शत-प्रतिशत भारतीय निर्यात पर अब कोई टैरिफ (सीमा शुल्क) नहीं लगेगा। वर्तमान में न्यूजीलैंड द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 450 उत्पादों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाता था। नए समझौते के तहत यह शुल्क खत्म हो जाएगा, जिससे भारतीय कपड़ा और परिधान, चमड़ा उद्योग,टोपी,चीनी मिट्टी के बर्तन (सिरेमिक्स), कालीन,और वाहन तथा उनके पुर्जों के निर्यात को भारी बढ़ावा मिलेगा। इसके एवज में,भारत ने भी न्यूजीलैंड से आने वाले 95 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दी है या उसे कम कर दिया है।

समझौते पर बोले वाणिज्य मंत्री

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा,'हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन हो रहा है, सीमाएं फिर से निर्धारित की जा रही हैं, राष्ट्र अपने साझेदार चुन रहे हैं और विभिन्न देश अपने भविष्य की राह तय कर रहे हैं। इस बदलते दौर में भारत और न्यूजीलैंड ने एक-दूसरे को चुना है। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता रिकॉर्ड 9 महीनों में संपन्न हुआ है। यह गति हमारे देशों के बीच गहरे विश्वास और साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। इस मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भारत के विकसित देशों के साथ संबंधों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमें प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के और करीब लाता है... पिछले साढ़े तीन वर्षों में यह मेरा सातवां मुक्त व्यापार समझौता है, और दो और समझौते होने बाकी हैं। अगले कुछ महीनों में यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ समझौते होंगे।

विदेशी निवेश और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा

व्यापार सुगमता के साथ-साथ इस एफटीए का एक प्रमुख स्तंभ विदेशी निवेश है। समझौते के तहत, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का भारी-भरकम निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) द्वारा भारत के साथ किए गए समझौते में प्रस्तावित 100 अरब डॉलर के निवेश ढांचे की तर्ज पर ही है। वहीं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम के तहत, भारत ने अपने संवेदनशील घरेलू कृषि और डेयरी सेक्टर को इस एफटीए के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा है। दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर जैसे सभी डेयरी उत्पादों के साथ-साथ अन्य कृषि उत्पादों पर आयात छूट नहीं दी गई है,जिससे भारतीय किसानों और स्थानीय डेयरी उद्योग के हितों की रक्षा सुनिश्चित हुई है।

आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी
राज्यसभा में भाजपा सांसद 106 से बढ़कर 113 हुए

नई दिल्ली,27 अप्रैल 2026। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के सात बागी सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की संख्या घटकर 3 रह गई है,जबकि बीजेपी सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। जो सात सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं,उनमें राघवचड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह,संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन सांसदों को बीजेपी के सदस्यों के रूप में दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को सभापति से सातों सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। संजय सिंह ने भी लेटर लिखकर उन्हें दलबदल कानून के उल्लंघन का दोषी बताते हुए अयोग्य घोषित करने की अपील की। संजय सिंह के मुताबिक, आम आदमी पार्टी ने एडवोकेट कपिल सिब्बल और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी अचारी सहित कई संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक सबसे पहले पार्टी को प्रस्ताव पास करके दूसरी पार्टी विलय करना पड़ेगा। कोई भी सांसद दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते।

3 सांसदों ने नितिन नवीन से मिलकर भाजपा जॉइन की : आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने शुक्रवार को बीजेपी जॉइन कर ली थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा सभापति को आवेदन देकर खुद को बीजेपी सांसद के रूप में मान्यता देने की मांग की थी,जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।

संपादकीय

होर्मुज बना आर्थिक युद्ध का अखाड़ा

इराजनीतिक परिवर्तन और ईरान का निरस्त्रीकरण करने के घोषित उद्देश्यों से शुरू किए अमेरिका के युद्ध को ईरान ने बड़ी चतुराई से आर्थिक जंग में बदल दिया है और होर्मुज जलमार्ग इस जंग का अखाड़ा बन गया है। ईरान को अपनी शर्तें मानने पर विवश करने के लिए उसकी सभ्यता मिटाने और पाषाण युग में पहुंचाने जैसी धमकियां देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप को अपना अंदाज बदलना पड़ा है। उनके बड़बोलेपन और धमकियों से नाराज ईरान ने दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए अनिच्छा दिखाई। इसके बाद ट्रंप को पहले अपने युद्धविराम की सीमा अनिश्चित काल के लिए बढ़ानी पड़ी और फिर लेबनान और इजरायल के युद्धविराम को भी आगे बढ़ाना पड़ा।

ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे अनुरोध किया था कि जब तक ईरान के प्रतिनिधि आपसी झगड़ा निपटाकर कोई साझा प्रस्ताव लेकर नहीं आते तब तक हमले रोक लें। ट्रंप ने कहा भी कि ईरान को वार्ता के लिए नेता तय करने में बेहद कठिनाई हो रही है। जंग में बुरी तरह हार रहे कट्टरपंथी और व्यवहारवादी नेताओं के बीच आपसी लड़ाई छिड़ गई है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पहले दौर की बातचीत के अनुभव के आधार पर इसकी पुष्टि की है।

ईरानी नेताओं के बीच आपसी झगड़े की बात को गत सप्ताह की इन अफवाहों से भी बल मिला कि समझौता वार्ताओं में ईरान का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद गलीबाफ मुख्य प्रतिनिधि के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह वार्ताओं की दिशा को लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल अहमद वहीदी के साथ गहराते मतभेद बताई गई। बताया जा रहा है कि पहले दौर की बातचीत में करार के तहत ईरान के 20 जहाजों के बदले ईरान के 20 जहाजों को होर्मुज से रास्ता देने का प्रस्ताव रखा था।

गलीबाफ उसके पक्ष में थे,लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने उसे रोक दिया। तब से उनके और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और मजलिस के कट्टरपंथी सदस्यों के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। उनके साथ-साथ विदेश मंत्री अब्बास अराघची को भी होर्मुज को खोलने के बयान और वार्ताओं के समर्थन में दिए कुछ बयानों की वजह से आड़े हाथों लिया जा रहा है। मतभेदों की इन अफवाहों को रोकने के लिए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को एक बयान जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने मतभेदों का खंडन करते हुए नेताओं के बीच फौलादी एकता की बात की।

ट्रंप ने हवाई हमलों से ईरान के परमाणु और मिसाइल तंत्र,वायुसेना प्रणाली और नौसेना को तो काफी हद तक नष्ट कर दिया,मगर रेवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज के तंत्र को और सत्ता पर उसके शिकंजे को ढीला नहीं कर पाए। बमबारी से मची तबाही के कारण जो लोग मुल्लाशाही के विरोध में थे,वे भी अब उसका समर्थन करने लगे हैं। बिजली और पानी के संयंत्रों और पुलों को नष्ट करने से अमेरिका और इजरायल के प्रति रोष और भड़क सकता था और यदि बदले में ईरान खाड़ी के देशों के जल और तेल संयंत्रों पर हमले करता तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाहाकार मच सकता था। शायद यही सोचकर ट्रंप ने ईरान की आय का मुख्य स्रोत बंद करने के लिए होर्मुज की नाकेबंदी की है। यह चाल उन्होंने जनरल मुनीर की राय पर इस उम्मीद से चली है कि आर्थिक तंगी से या तो ईरान बातचीत के लिए विवश हो जाएगा या फिर आपसी फूट से वहां सत्तापलट हो जाएगा।

कानून हैं,योजनाएं हैं,फिर भी सीवर में मौतें,आखिर जिम्मेदार कौन?

प्रो.आर.के.जैन 'अरिजीत'
बड़वानी,मध्यप्रदेश

सफाई कर्मी नहीं,यह व्यवस्था की सबसे अनदेखी लड़ाई के सिपाही हैं

स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चेहरा : सीवर में छिपी असुरक्षित सच्चाई

शहरों की चमक जब स्वच्छता के दावों से आत्ममुग्ध होकर दमकती है, उसी क्षण उसी चमक के भीतर छिपा अंधकार चुपचाप इंसानी जिंदगियों को निगलता चला जाता है। मार्च 2026 की शुरुआत में स्वच्छता के शिखर पर खड़े इंदौर में,चोइथराम मंडी गेट के पास एक सीवर चैंबर दो जिंदगियों का अंत बन गया–करण यादव और अजय डोडी जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से काल के गाल में समा गए। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के वे उस घातक गहराई में उतरे; एक के अचेत होते ही दूसरा उसे बचाने भीतर गया,पर दोनों ही वापस नहीं लौट सके। यह घटना महज एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा नहीं,बल्कि उस विफल व्यवस्था की कठोर सच्चाई है, जो अपने सबसे कमजोर कर्मियों को सुरक्षित रखने में बार-बार असफल साबित हो रही है।

पीड़ा की यह आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कुछ ही सप्ताह बाद 15 अप्रैल 2026 को हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में वही भयावह दृश्य फिर दोहराया गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के ठेकेदार ने तीन मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतार दिया,जहां जहरीली गैसों ने दो जीवन–राजेंद्र कुमार और अब्दुल कलाम–को निगल लिया, जबकि तीसरा मजदूर गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचा। इस तरह की लगातार होती घटनाएं यह साफ संकेत देती हैं कि यह कोई अपवाद नहीं,बल्कि एक खतरनाक और स्थापित होती जा रही व्यवस्था बन चुकी है। देश के अलग-अलग कोनों में फैली यह मौतें बार-बार यह कठोर सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कब तक गरीब मजदूर अपनी जान की कीमत पर हमारी स्वच्छता की जिम्मेदारी ढोते रहेंगे।

संवैधानिक अधिकारों और मानव गरिमा की रक्षा के दावों के बीच भी इन घटनाओं की अनदेखी संभव नहीं रह सकी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदौर मामले पर 5 मार्च 2026 और नूह मामले पर 24 अप्रैल 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर स्पष्ट किया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरना मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। रिपोर्ट में सुरक्षा उपकरणों की कमी, ठेकेदारी व्यवस्था की खामियां और मुआवजे की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। यह हस्तक्षेप दिखाता है कि यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और प्रशासनिक विफलता का परिणाम भी है।

सांख्यिकीय सच्चाइयों की परतें जैसे-जैसे खुलती हैं, यह संकट और अधिक भयावह रूप लेता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार 2014 से 2025 के बीच 859 सफाई कर्मियों की जान सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में गई। 2017 से मार्च 2026 तक 622 मौतें दर्ज हुईं,जबकि 2026 के पहले चार महीनों में ही 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़े अक्सर कम बताते हैं, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है। हर साल औसतन 80 से 130 सफाई कर्मी हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसों से दम घुटने के कारण जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं,बल्कि उन परिवारों की टूटी हुई कहानियां हैं जिन्होंने अपने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है।

कानूनों और न्यायिक आदेशों की मौजूदगी के बावजूद जमीन पर बदलाव न दिखना इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। 2013 का मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध और पुनर्वास अधिनियम इस अमानवीय प्रथा पर रोक लगाता है,जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मैकेनाइज्ड सफाई अनिवार्य करते हुए मृतक परिवारों को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। फिर भी इंदौर और नूह मामलों में मुआवजे की घोषणा के बावजूद सवाल बना रहता है कि क्या केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त है? ठेकेदारों की लापरवाही,सुरक्षा उपकरणों की कमी और कमजोर निगरानी व्यवस्था इन कानूनों को कागजों तक सीमित कर देती है।

घोषित नीतियों और धरातल की सच्चाई के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन-2 और 'नमास्ते'जैसी योजनाओं में मैकेनाइज्ड सफाई तथा सफाई कर्मियों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है,जिसके लिए हजारों करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। इसके बावजूद इंदौर जैसे शहरों में आधुनिक मशीनें होते हुए भी उनका नियमित उपयोग नहीं किया जाता, जबकि नूह जैसे क्षेत्रों में ठेकेदार जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। सस्ती मजदूरी के लालच में मानव जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है और इस पूरे तंत्र का सबसे भारी बोझ दलित समुदाय पर पड़ता है,जो आज भी सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा झेल रहा है। इस संकट के समाधान की मांग अब केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस और कठोर कदम उठाए जाएं। हर शहर में 100 प्रतिशत मैकेनाइज्ड सफाई अनिवार्य हो, ताकि कोई मजदूर जान जोखिम में डालकर सीवर में न उतरे। ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई–भारी जुर्माना,ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी दंड–तुरंत लागू किया जाए। प्रत्येक मृत्यु पर 30 लाख रुपये मुआवजा,परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही सफाई कर्मियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, बीमा और प्रशिक्षण अनिवार्य हों, ताकि उनकी सुरक्षा और सम्मान वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो सके।

यह स्थिति हमारी सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी पर सीधा प्रश्न उठाती है कि जब हर महीने सफाई कर्मी जान गंवा रहे हैं, तो स्वच्छता अभियान वास्तव में किसके लिए है। इंदौर जैसे स्वच्छता के प्रतीक शहर और नूह जैसे क्षेत्र भी इस त्रासदी से अछूते नहीं हैं,तो छोटे शहरों और गांवों की स्थिति सहज ही समझी जा सकती है। यदि इन अज्ञात नायकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी,तो हमारी उपलब्धियां खोखली साबित होंगी। अब समय है कि नारों से आगे बढ़कर वास्तविक कदम उठाए जाएं, अन्यथा हर मौत हमें याद दिलाती रहेगी कि स्वच्छता की कीमत किसी और की जिंदगी है।

पहाड़ों की नई जीवन रेखा,दुर्गम क्षेत्रों में सड़क क्रांति और विकसित भारत

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़

भारत की भौगोलिक संरचना जितनी विविधतापूर्ण है,उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। उत्तर के ऊंचे हिमालयी शिखरों से लेकर उत्तर-पूर्व की दुर्गम पहाड़ियों तक,एक समय था जब विकास की किरणें इन दुर्गम क्षेत्रों की चोटियों पर पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देती थीं। लेकिन आज परिदृश्य बदल चुका है। वर्तमान में सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों तक पहुँचती सड़कें केवल डामर और कंक्रीट का जाल नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्र रूपी शरीर की शिराएं और धमनियांबन चुकी हैं।जिस प्रकार मानव शरीर में धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक पहुँचाती हैं और शिराएं उसे वापस लाती हैं,ठीक उसी प्रकार ये सड़कें देश के मुख्य आर्थिक केंद्रों को सुदूर गांवों से जोड़ रही हैं।आर्थिक गतिशीलता,इन सड़कों के माध्यम से पहाड़ों का स्थानीय उत्पाद,चाहे वह जैविक फल हों, हस्तशिल्प हो या जड़ी-बूटियाँ,अब सीधे बड़े बाजारों तक पहुँच रहा है। यह रक्त का वह प्रवाह है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर रहा है। पहले एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए कई किलोमीटर पालकी या कंधे पर ढोना पड़ता था। आज एंबुलेंस सीधे घर के दरवाजे तक पहुँच रही है। दुर्गम क्षेत्रों के बच्चे अब उच्च शिक्षा के लिए शहरों से बेहतर तरीके से जुड़ पा रहे हैं।भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का जाल बिछना केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। सीमा सड़क संगठन जैसी संस्थाएं कठिन परिस्थितियों में भी ऐसी सड़कों और सुरंगों (जैसे अटल टनल) का निर्माण कर रही हैं, जो हर मौसम में संपर्क बनाए रखती हैं। सड़क केवल दो स्थानों को नहीं जोड़ती, बल्कि यह दो संस्कृतियों,दो उम्मीदों और अंत्योदय के संकल्प को भी जोड़ती है। परिदृश्य तेज़ी से बदला है,सुविधाएं अब आमजन की पहुंच में हैं। विकसित भारत के विजन में कनेक्टि विटी सबसे बड़ा स्तंभ है। जब सड़कें सुदूर गांव तक पहुँचती हैं,तो अपने साथ निम्नलिखित सुविधाएं भी लाती हैं।

डिजिटल इंडिया का विस्तार दिखाई देता है,सड़क के साथ-साथ ऑप्टि कल फाइबर बिछाना आसान हो जाता है,जिससे पहाड़ों में इंटरनेट पहुँच रहा है।

पर्यटन को बढ़ावा मिला है,ग्रामीण पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।
पलायन पर रोक लगी है,जब सुविधाएं और रोजगार गांव में ही मिलने लगते हैं, तो शहरों की ओर होने वाला मजबूर पलायन कम होने लगा है।

सड़कों का यह बढ़ता जाल इस बात का प्रमाण है कि विकास अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। देश के सबसे पिछड़े और दुरूह इलाकों तक पहुँचती ये धमनियां राष्ट्र के शरीर में ऊर्जा का नया संचार कर रही हैं। यह बदलता बुनियादी ढांचा इस बात की गारंटी है कि विकसित भारत की यात्रा में कोई भी नागरिक और कोई भी क्षेत्र पीछे नहीं छूटेगा। आज पहाड़ केवल देखने में सुंदर नहीं रहे, बल्कि वे रहने और विकास करने के लिए भी सुलभ हो गए हैं।

हीट एक्शन प्लान को गंभीरता से लागू करना होगा

सुभाष बुड़ावन वाला,
रतलाम,मध्यप्रदेश

दुनिया के शहरों पर एक ऐसा संकट तेजी से गहराता जा रहा है,जो दिखाई कम देता है लेकिन असर सबसे ज्यादा करता है, खतरनाक गर्मी। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक शहरी इलाकों में अत्यधिक गर्मी से प्रभावित गरीबों की संख्या में लगभग 700त्न तक की वृद्धि हो सकती है। यह आंकड़ा सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले शहरी भविष्य की भयावह तस्वीर है,खासकर ग्लोबल साउथ, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तेजी से बढ़ते शहरों के लिए।

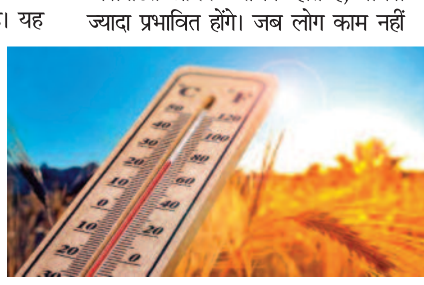

गर्मी का यह संकट सीधे तौर पर क्लाईमेट चेंज और अनियोजित शहरीकरण से जुड़ा है। शहरों में कंक्रीट, डामर और धातु की अधिकता प्राकृतिक हरियाली को खत्म कर देती है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा होता है। इसके कारण शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो सकता है। यह अंतर रात के समय और भी खतरनाक हो जाता है, जब शरीर को ठंडक नहीं मिलती और हीट स्ट्रेस बढ़ता है।

इसका सबसे बड़ा असर गरीब आबादी पर पड़ता है। झुग्गी-झोपड़ियों या घनी बस्तियों में रहने वाले लोग न तो पर्याप्त वेंटिलेशन पा पाते हैं और न ही एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाईजेशन के अनुसार अत्यधिक गर्मी हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनती है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हीटवेव के दौरान डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 2023 और 2024 में भारत,यूरोप और अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने हजारों लोगों की जान ली,जिससे यह साफ हो गया कि यह समस्या अब भविष्य की नहीं,वर्तमान की है।

आर्थिक दृष्टि से भी यह संकट गंभीर है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार 2030 तक अत्यधिक गर्मी के कारण वैश्विक स्तर पर करोड़ों वर्किंग आवर्स नष्ट हो सकते हैं। निर्माण,कृषि, परिवहन और छोटे व्यापार जैसे सेक्टर, जहां गरीब और असंगठित श्रमिक अधिक होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जब लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी आय घटेगी,जिससे गरीबी और असमानता और बढ़ेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। अत्यधिक गर्मी में स्कूल बंद करने पड़ते हैं या बच्चों की उपस्थिति घट जाती है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव बढ़ता है। बिजली की मांग चरम पर पहुंच जाती है,जिससे बार-बार पावर कट होते हैं, और यही चक्र समस्या को और गंभीर बना देता है।

हालांकि,समाधान मौजूद हैं, और यही इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। शहर यदि समय रहते कदम उठाएं तो इस संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एक प्रमुख उपाय है। शहरों में पेड़-पौधे,पार्क,ग्रीन कॉरिडोर और जल स्रोत तापमान को स्वाभाविक रूप से कम करते हैं। शोध बताते हैं कि घने हरित क्षेत्र आसपास के तापमान को 2 से 4 डिग्री तक घटा सकते हैं।

इसी तरह कूल रूफ तकनीक, जहां छतों को सफेद या रिफ्लेक्टिव पेंट से ढका जाता हैभी बेहद प्रभावी है। भारत के अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों में इस मॉडल को अपनाने से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके अलावा, सस्ती और ऊर्जा-कुशल कूलिंग तकनीकों को गरीबों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है,ताकि वे भी इस बढ़ती गर्मी से खुद को बचा सकें।

शहरी नियोजन में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संकरी गलियों,ऊंची इमारतों और कम वेंटिलेशन वाले क्षेत्रों की बजाय ऐसे डिजाइन को बढ़ावा देना होगा जो हवा के प्रवाह को बढ़ाए और गर्मी को कम करे। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, प्रदूषण कम करना और जल संरक्षण को प्राथमिकता देना भी इस दिशा में अहम कदम हैं।

नीतिगत स्तर पर सरकारों को हीट एक्शन प्लान को गंभीरता से लागू करना होगा। भारत के कई शहरों में इस तरह के प्लान शुरू किए गए हैं, जिनमें हीटवेव की चेतावनी, पानी की उपलब्धता और कूलिंग सेंटर की व्यवस्था शामिल है। लेकिन इन्हें व्यापक और प्रभावी बनाने की जरूरत है, खासकर उन इलाकों में जहां सबसे अधिक जोखिम है।

यह समझना होगा कि गर्मी अब केवल एक मौसम नहीं रही, यह एक बहुआयामी संकट बन चुकी है, जो स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को एक साथ प्रभावित कर रही है। अगर आज ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो 2050 तक शहर सचमुच हीट ट्रैप बन सकते हैं, जहां जीना मुश्किल होगा, खासकर गरीबों के लिए।

यह समय चेतावनी को सुनने और कार्रवाई करने का है। शहरों को टिकाऊ, हरित और समावेशी बनाना ही इस साइलेंट किलर से लड़ने का एकमात्र रास्ता है। वरना आने वाला भविष्य केवल अधिक गर्म ही नहीं, बल्कि अधिक असमान और असुरक्षित भी होगा!

आखिर कब तक

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

गुनहगार पाप के कर्मों के फल से बचेगा आखिर कब तक
बेईमानी से कमाए हुए धन को कोई पचाएगा कब तक!
आखिर तो सच ही जीतेगा झूठ जीतता रहेगा कब तक
वक्त तो बदलता रहता है बुरा वक्त चलता रहेगा कब तक।
लोगों को बेवकूफ बनाकर राजनेता वोट लेंगे कब तक
सच्चाई तो बाहर आएगी अफवाहें चलेंगे कब तक!
समझदारी से काम लेना ही पड़ेगा बेवकूफ बनेंगे कब तक
आखिर तो शांति बहाल होगी यूं लड़ाई चलती रहेगी कब तक!
आखिर तो अपने काम आएंगे बेगानों पर निर्भर रहेंगे कब तक
आखिर तो बसंत आएगा ही पतझड़ चलती रहेगी कब तक!
आखिर तो भाग्य का सूरज निकलेगा अंधेरा डराएगा कब तक
आखिर तो चांद सामने आएगा बादलों में छुपा रहेगा कब तक।
आखिर तो शराफत कायम होनी है गुंडागर्दी चलती रहेगी कब तक
आखिर तो इंसाफ होगा ही दमन चक्कर चलता रहेगा कब तक।
धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता इस तरह अंधेरा छाया रहेगा कब तक
जैसे भी हो चलते रहो मंजिल तक जाने में रुकावटें रोकेंगी कब तक।

चिरई चुरगुन के पियास बुझावव

प्रीतम कुमार साहू(गुरुजी)
धमतरी,छत्तीसगढ़

चिरई चुरगुन के चिंव-चिंव बोली अउ फुँदक फुँदक के रेंगना हर घाते सुग्घर लागथे । प्राकृतिक सौंदर्य हर चिरई चुरगुन ले हवय ।चिरई चुरगुन बिना जंगल झाड़ी अउ महल अटारी ह सुन्ना लागथे ।

फेर गरमी दिन म नदियाँ नरवा,तरिया,डबरी सबो ह सुखा जाथे त चिरई चुरगुन मन बूँद-बूँद पानी बर तरसत रहि जाथे। कतकोंन चिरई मन तो दाना पानी बिना अपन परान ल तियाग देथे। ऐसना समय म चिरई चुरगुन के जीव ल बचाय बर उदिम कर सकथन अपन घर के छत छानी मा,बारी बखरी मा अउ जेन मेर रुख राई हे तेन मेर सकोरा म दाना पानी राख के चिरई चुरगुन के पियास ल बुझा स सकथन। जेकर ले लहकत घाम म उड़त परकी परेवना अउ जम्मों चिरई चुरगुन मन अपन पियास ला बुझा सके।आज कल तो सहर तो बहुत दूरिहा के बात आय गांव म घलोक आघु कस चिरई चुरगुन देखे बर नइ मिलय। दिनों दिन चिरई चुरगुन मन कम होवत जात हे। जेन हर पर्यावरण संतुलन बर बने बात नो आय। विलुपत चिरई चुरगुन ल हमला बचाय ल परही सँगवारी हो।

ए दुनिया म जतेक महत्तम मनखे मन के हे ओतकेच महत्तम चिरई चुरगुन मन के घलोक हवय। प्राकृतिक समपदा के भोग करें के अधिकार सिरिफ मनखेमन बस ल नइ हे,सबो जीव मन ला उपभोग करें के अधिकार हवय।प्राकृतिक संतुलन ल बनाय रखे बर सबो जी के अब्बर महत्तम हे।

फेर कतकोन मनखेमन ह अपन आप ला सुजानीक समझ के दुसर जीव उपर अतिचार करत रहिथे। जंगल के आधा जीव जंतु मन हर तो मार के खवई म सिरागे। अउ आधा जेन हर बाचे हावय वहू मन के जीव ल खतरा बने रहिथे।

ए दुनिया म सिरफ मनखे हर ऐसन जीव आए जेन हर सबो जीव के जान ल बचा सकत हे। फेर मनखे हर सुवारथ म अनधरा हो के दूसर जीव मन उपर अतिचार करत सिकार करे म लगे रहिथे।

दिनों दिन चिरई चुरगुन मन कम होत जात हे। जेन ल बचाय के जिम्मेवारी मनखे मन के हवय ।मनखेमन हर त अपन खाय पिये के अउ जिनगी जिए बर नाना परकार के नवा नवा उदीम कर डारे हावय। फेर एसना नवा नवा उदिम का कोनो चिरई चुरगुन बर कोनो करय हावय ? बिरले मनखे मन करत हवय ! एकरे सेती सँगवारी हो चिरई चुरगुन के पियास बुझाय बर अउ विलोपत होवत चिरई चुरगुन ल बचाय बर अपन अपन घर के छत छानी म,बारी बखरी म,अउ जेन मेर रुख राई हे तेन मेर सकोरा म दाना पानी राखव । जेकर ले चिरई चुरगुन मन अपन भूख पियास ला मिटा के अपन जिनगी ल बचा सकय।

यादों की उठी अर्थी

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

वह दोपहर किसी सड़ी हुई कढ़ी जैसी चिपचिपी थी। कार के भीतर का तापमान और मेरी पत्नी सुजाता के तेवर,दोनों ही चालीस डिग्री के पार थे। सामने डैशबोर्ड पर रखा मोबाइल फोन किसी देवता की तरह चमक रहा था, जिसमें एक निर्जीव स्त्री की आवाज़ हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा रही थी। अगले सौ मीटर पर बाएं मुड़ें, उस आवाज़ में वह भरोसा था जो अक्सर धोखेबाज वकीलों की बातों में होता है। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, पर सामने सड़क नहीं, एक गहरा नाला था जो शहर की सारी गंदगी समेटे इतिहास की तरह बह रहा था। सुजाता ने ठंडी आह भरी, मैंने कहा था न, वह दाहिने कह रही है, तुम हमेशा औरतों को गलत समझते हो। मैंने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा,वह नीली रेखा अब किसी घायल सांप की तरह छटपटा रही थी। मुझे लगा जैसे वह नक्शा नहीं,मेरा चरित्र प्रमाण पत्र है, जिसे एक उपग्रह अंतरिक्ष से बैठकर लिख रहा है।

री-रूटिंग...फोन से आवाज़ आई। यह शब्द सुनते ही सुजाता का चेहरा ऐसा हो गया जैसे मैंने उसकी शादी का गहना गिरवी रख दिया हो। देखो,यह मशीन भी मान रही है कि तुम भटक गए हो। इसे दोष मत दो,यह तो विज्ञान है। तुम्हारी बुद्धि ही पत्थर की हो गई है। गाड़ी अब एक ऐसी संकरी गली में थी जहाँ धूप भी घुसने से पहले दो बार सोचती होगी। बगल की दुकान पर बैठे एक बूढ़े ने हमें ऐसे देखा जैसे हम किसी दूसरे ग्रह से आए शरणार्थी हों। मैंने चीखकर कहा, यह बाएं बोल रही है, पर यहाँ तो दीवार है! सुजाता ने मोबाइल छीन लिया और उसे अपनी छाती से ऐसे लगा लिया जैसे वह उसका सर्वस्व हो। बेचारी को डराओ मत, वह सही कह रही है,तुमने ही इसे ठीक से पकड़ा नहीं होगा। देखो,वह रो रही है! वास्तव में, स्क्रीन पर पसीने की एक बूंद गिरी थी, जो सुजाता के विलाप का हिस्सा लग रही थी।

कार अब एक सुनसान श्मशान घाट के गेट पर खड़ी थी। जीपीएस की वह स्त्री अब फुसफुसा रही थी, आप गंतव्य पर पहुँच चुके हैं। चारों तरफ खामोशी थी,सिवाय इंजन की गड़गड़ाहट और सुजाता की सिसकियों के। देखा? पहुँच गए न? अब खुश हो? अपनी जिद के चक्कर में तुमने इसे भी पागल कर दिया। उसने फोन को डैशबोर्ड पर पटक दिया। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हम यहाँ क्यों आए? हमें तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में जाना था, जो शहर के सबसे बड़े होटल में था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वहाँ कोई लाइट नहीं थी,कोई संगीत नहीं था। बस कुछ टूटी हुई कब्रें थीं और उन पर जमी धूल। सुजाता ने ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, तुमने इस बेचारी मशीन को इतना प्रताड़ित किया कि इसने हार मान ली। तुमने इसे गलत साबित करने के लिए पूरा रास्ता ही बदल दिया!

मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन धुंधली थी। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी। वहाँ एक सफेद लिफाफा रखा था। वह शादी का कार्ड नहीं था। वह मेमोरी लॉस और अल्जाइमर की मेडिकल रिपोर्ट थी,जिस पर मेरा नाम बड़े अक्षरों में लिखा था। अचानक बिजली की तरह एक कौंध गई। होटल? शादी? वह तो पिछले साल हो चुकी थी। तभी मेरी नज़र बगल वाली सीट पर पड़ी–वह खाली थी। वहाँ न सुजाता थी, न उसकी सिसकियाँ,बस उसकी एक पुरानी बनारसी साड़ी की गंध हवा में तैर रही थी। अचानक बिजली की तरह दिमाग में एक कौंध गई और दिल की धड़कनें किसी ढहती इमारत की तरह बैठ गईं। सुजाता को मरे हुए तो तीन साल बीत चुके थे;इसी श्मशान की आग ने उसे राख में बदला था। अल्जाइमर के अंधेरे गलियारों में भटकता मेरा दिमाग हर बार जीपीएस की उस नीली रेखा को सुजाता की आवाज़ समझ बैठता था। मैं हर शाम अपनी यादों के मलबे में दबी उसकी चिता तक खिंचा चला आता था। वह मशीन गलत नहीं थी, मेरा अस्तित्व ही री-रूटिंग के जाल में फंसा था। उस निर्जन कब्रिस्तान में फोन फिर बोल उठा–गंतव्य पर पहुँच चुके हैं। सामने सुजाता की चिता जल रही थी। मैं अपनी ही याददाश्त की अर्थी उठाए खड़ा था। फोन पर वही नीली रेखा अब स्थिर हो चुकी थी। फोन से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने खुद से पूछा, बाएं मुड़ना था या दाएं? तभी जीपीएस की आवाज़ फिर गूंजी,वापस मुड़ें,आप फिर से अपनी यादों के गलत मोड़ पर आ गए हैं। उस सन्नाटे में मुझे अहसास हुआ कि मैं जीपीएस को गलत नहीं ठहरा रहा था,मैं तो उस हकीकत से लड़ रहा था जो मेरी सुध-बुध के साथ ही दफन हो चुकी थी। कार वहीं खड़ी थी,और मैं मैप की उस आखिरी बिंदु पर था,जहाँ से आगे कोई सड़क नहीं थी,सिर्फ एक गहरा अंधेरा था।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

अम्बिकापुर अग्निकांड के बाद बड़ा सवाल : घनी आबादी के बीच खतरनाक कारोबारों पर कार्रवाई कब?

आग वाली बिल्डिंग पर निगम नोटिस,शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर नई बहस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
राम मंदिर रोड स्थित भीषण अग्निकांड के बाद शहर में अब सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक कार्रवाई और घनी आबादी के बीच संचालित खतरनाक कारोबारों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। एक ओर प्रशासन हादसे की जांच में जुटा है,वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा आग प्रभावित भवन को असुरक्षित घोषित कर हटाने संबंधी नोटिस जारी किए जाने के बाद लोगों ने शहरभर के संवेदनशील स्थानों पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि एक प्रतिष्ठान में लगी आग ने पूरे इलाके को दहला दिया, तो उन स्थानों पर संभावित खतरा कितना बड़ा हो सकता है, जहां प्रतिदिन पेट्रोल,डीजल,गैस सिलेंडर, लकड़ी,प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री का भंडारण होता है।

निगम नोटिस के बाद उठे सवाल

नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में आग प्रभावित भवन को जर्जर,असुरक्षित एवं अनुपयुक्त बताते हुए हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद शहर में यह चर्चा तेज हो गई है कि जब हादसे के बाद कार्रवाई हो सकती है,तो पहले से चिन्हित जोखिम वाले स्थानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लोगों का कहना है कि शहर में कई जगह घनी आबादी के बीच ऐसे प्रतिष्ठान वर्षों से संचालित हो रहे हैं, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

पेट्रोल पंप और गैस गोदाम सबसे संवेदनशील

विशेषज्ञों के अनुसार रिहायशी इलाकों के बीच संचालित पेट्रोल पंप और गैस गोदाम अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। यहां छोटी सी चूक,रिसाव,शॉर्ट सर्किट या आगजनी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर संकरी सड़कें,भारी भीड़ और आसपास मकान होने के कारण आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य भी बाधित हो सकता है।

लकड़ी मील,प्लास्टिक गोदाम और कबाड़ केंद्र भी खतरे में...

शहर के भीतर लकड़ी मील, प्लास्टिक गोदाम, कबाड़ केंद्र और अन्य ज्वलनशील व्यवसाय भी संचालित हैं। ऐसे स्थानों पर आग लगने की स्थिति में लपटें तेजी से फैल सकती हैं और आसपास के घरों व दुकानों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। नागरिकों ने इन प्रतिष्ठानों की समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण कराने की मांग की है।

क्या प्रशासन बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है?

नागरिकों ने सवाल उठाया है कि क्या हर बार प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही सक्रिय होगा? क्या पहले चेतावनी, निरीक्षण और नियमन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? लोगों का कहना है कि हर घटना के बाद जांच समिति, नोटिस और बयान सामने आते हैं,लेकिन जमीनी स्तर पर स्थायी समाधान दिखाई नहीं देता।

शहरव्यापी सर्वे और सुरक्षा जांच की मांग : अग्निकांड के बाद शहरवासियों ने मांग की है कि प्रशासन पूरे शहर का सर्वे कर यह चिन्हित करे कि कौन-कौन से संवेदनशील प्रतिष्ठान घनी आबादी के बीच संचालित हो रहे हैं। साथ ही–

अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता जांची जाए

- लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा हो।
- सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- जोखिम वाले प्रतिष्ठानों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।
- आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए।

हादसे के बाद नहीं, पहले जागे सिस्टम

स्थानीय लोगों का कहना है कि जरूरत हादसे के बाद कार्रवाई की नहीं, बल्कि हादसे से पहले रोकथाम की है। यदि समय रहते जोखिम वाले स्थानों की पहचान कर नियमन किया जाए, तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है।

शहर अब जवाब चाहता है...

अम्बिकापुर की जनता अब पूछ रही है–

- घनी आबादी के बीच खतरनाक कारोबारों को अनुमति किस आधार पर मिली?
- सुरक्षा मानकों की अंतिम जांच कब हुई थी?
- क्या प्रशासन बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है?
- क्या अग्निकांड के बाद शहरभर में व्यापक सुरक्षा अभियान चलेगा?

राम मंदिर रोड हादसे ने सिर्फ एक दुकान की आग नहीं दिखाई,बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

छत्तीसगढ़ की बेटी शिवानी सोनी ने रचा इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' से सम्मानित

प्रदेश की प्रतिभा का विश्व स्तर पर बढ़ा गौरव

मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुलाकात कर दी बधाई...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
अंबिकापुर की प्रतिभाशाली गोल्फ खिलाड़ी शिवानी सोनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हुए नया इतिहास रच दिया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी के रूप में शिवानी सोनी को 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' द्वारा सम्मानित किया गया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने उनसे मुलाकात कर बधाई दी तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

बेटियों की सफलता पर पूरे समाज को गर्व : मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि जब बेटियां अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से सफलता के नए आयाम स्थापित करती हैं,तो पूरा समाज गर्व महसूस करता है। शिवानी सोनी की यह उपलब्धि न केवल युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभा का वैश्विक मंच पर सशक्त प्रमाण भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और ऐसे खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का संकल्प : इस अवसर पर शिवानी सोनी ने मंत्री श्री अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वह आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी मेहनत करेंगी।

पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल

शिवानी सोनी की इस उपलब्धि से अंबिकापुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी और गर्व का माहौल है। उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगी।

आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से बदलेगा लखनपुर नगर पंचायत का स्वरूप

कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने 283 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं का किया भूमिपूजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
नगर पंचायत लखनपुर के विकास को नई दिशा देने की पहल करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने 283 लाख रुपये की लागत से पूर्ण होने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लखनपुर का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इन योजनाओं से नगर की आधारभूत संरचना और अधिक मजबूत होगी।

नागरिकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं : मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि लखनपुर आने वाले समय में आधुनिक और सुव्यवस्थित नगर के रूप में उभरेगा।

सड़क,नाली और सामुदायिक ढांचे पर होगा कार्य : भूमिपूजन की गई परियोजनाओं में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सामुदायिक अधोसंरचना सहित कई आवश्यक विकास कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं नगर की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार भी बनेंगी।

विकास की गति लगातार रहेगी जारी : मंत्री श्री अग्रवाल ने नगर पंचायत लखनपुर के नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार जनहित के कार्यों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और भविष्य में भी विकास की यह गति लगातार जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार : इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से ही लखनपुर को यह महत्वपूर्ण सौगात प्राप्त हुई है।

क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल :

विकास कार्यों को लेकर स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखा गया। लोगों ने आशा जताई कि इसी तरह क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य होते रहेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

अग्निवीर भर्ती परीक्षा हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण 1 मई से आयोजित

इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

-संवाददाता-
बलरामपुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा (सीईई) की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए जारी अधिसूचना के तहत 10 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पंजीकृत अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 01 जून 2026 से 15 जून 2026 के मध्य संभावित है। परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलरामपुर द्वारा 01 मई 2026 से 31 मई 2026 तक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक पंजीकृत अभ्यर्थी रोजगार विभाग के पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलरामपुर के सूचना पटल का अवलोकन अथवा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण हेतु 28 से 30 अप्रैल तक विशेष शिविर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर जिले में 28, 29 एवं 30 अप्रैल को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान भारत कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे। हितग्राही आधार कार्ड एवं राशन कार्ड लेकर पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंच सकते हैं। योजना के तहत पात्र परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

नवाचार से चमका सरगुजा : शिक्षिका आराधना तिवारी को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान सह शैक्षिक संप्रवाह 2025-26 का भव्य आयोजन राजधानी रायपुर स्थित स्वामी आत्मानंद प्रो. जे. एन. पाण्डेय शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय में संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित समारोह में सरगुजा जिले से 6 शिक्षकों का चयन किया गया, जिनमें अंबिकापुर की शिक्षिका श्रीमती आराधना तिवारी का नाम प्रमुख रहा। श्रीमती आराधना तिवारी वर्तमान में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसा में पदस्थ हैं। उन्हें यह सम्मान उनके अभिनव प्रयास दीवार पत्रिका 'अभिव्यक्ति' के लिए प्रदान किया गया। इस नवाचार से विद्यालय के बच्चों में रचनात्मक लेखन,अभिव्यक्ति क्षमता और समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष उल्लेखनीय है कि परसा विद्यालय के छात्र-छात्राओं की रचनाएं लगातार राष्ट्रीय स्तर की बाल विज्ञान पत्रिका चकमक में चयनित हो रही हैं, जो पूरे सरगुजा संभाग के लिए गर्व का विषय है। जिस क्षेत्र को कभी पिछड़े क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, वहीं आज बच्चे अपनी प्रतिभा और सृजनशीलता से राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। रायपुर के मंच से अपनी प्रस्तुति देते हुए श्रीमती तिवारी ने बताया कि पहले बच्चे लेखन से झिझकते थे,लेकिन अब अपने साथियों की सफलता देखकर प्रेरित हो रहे हैं। दीवार पत्रिका बच्चों के लिए सीखने का सशक्त माध्यम बन चुकी है और विद्यालय में उनकी उपस्थिति बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। उन्होंने राज्य के सभी शिक्षकों से अपने-अपने विद्यालयों में इस प्रकार की दीवार पत्रिकाओं के निर्माण एवं उपयोग की अपील की। साथ ही राष्ट्रीय नवाचारी समूह भारत एवं आयोजन समिति को योग्य शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्था प्रमुख एस. सूर्यवंशी ने बताया कि इस वर्ष राज्यभर से लगभग 700 आवेदन प्राप्त हुए थे,जिनमें से 160 शिक्षकों का चयन तीन चरणों की प्रक्रिया के बाद किया गया। यह संस्था उन शिक्षकों को मंच देती है,जो शासकीय सम्मानों से वंचित रह जाते हैं। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के उप सचिव श्री पी. रघु, समग्र शिक्षा के उप संचालक ए. के. सारस्वत,जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती, डीएमसी अरुण कुमार शर्मा एवं प्राचार्य सुचिता पाण्डेय की गरिमामयी उपस्थिति रही। सरगुजा जिले से चयन कार्य में श्री सुनील कुमार यादव,श्री लव कुमार कश्यप,सुश्री अंजली बड़ा एवं श्री संदीप पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।

लखनपुर तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन..गो-रक्षा हेतु ठोस कदम उठाने की मांग

-संवाददाता-
लखनपुर,27 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
'राष्ट्रमाता गो-सम्मान आह्वान अभियान' के तहत कार्यकर्ताओं ने गो-रक्षा एवं गोवंश संरक्षण को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम संबोधित है, जिसे तहसीलदार के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का अनुरोध किया गया।

गोवंश संरक्षण पर जताई चिंता : ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संतुलन में गाय का विशेष महत्व रहा है, लेकिन वर्तमान समय में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन में कमी आने से उनकी स्थिति चिंताजनक होती जा रही है।

सरकार से की ठोस कार्रवाई की मांग : कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि गो-रक्षा, गो-सेवा एवं गोवंश संरक्षण के लिए प्रभावी एवं ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि गोवंश सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।

ये रहे उपस्थित कार्यकर्ता : ज्ञापन सौंपने वालों में दिनेश साहू, रवि भूषण पांडेय, प्रदीप गुप्ता, विक्रम सिंह, सुभाष अग्रवाल, यतेंद्र पांडेय, सुरेश साहू, लक्ष्मण साहू, सुरेन्द्र साहू, कामेश्वर राजवाड़े, अजय सिंह, सुनील ठाकुर एवं अखिलेश राजवाड़े शामिल रहे।

जनभागीदारी की अपील : कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार से आग्रह किया कि ज्ञापन को उचित माध्यम से देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाए। साथ ही आम नागरिकों से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। यह अभियान गोवंश को राष्ट्रमाता के रूप में सम्मान दिलाने तथा उनकी रक्षा के लिए जनजागरण का हिस्सा बताया गया।

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से समय लाल को मिली राहत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत थोर निवासी समय लाल को मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से बड़ी राहत मिली है। उनका 61 हजार 149 रुपये का बिजली बिल बढ़ गया था, जिसे भरना उनके लिए मुश्किल था। योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने शिविर में पंजीयन कराया। इसके बाद उनका 54 हजार 450 रुपये बिजली बिल माफ कर दिया गया। शेष 7 हजार 700 रुपये जमा कर समय लाल चिंतामुक्त हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि योजना से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

रेफर महिला ने एंबुलेंस में दिया बच्चे को जन्म,मां की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
कुसमी अस्पताल से रेफर महिला का प्रसव रास्ते में एंबुलेंस में ही हो गया। लेकिन महिला की जान नहीं बची। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि बच्चा स्वस्थ्य है। जानकारी के अनुसार सैदुन खातुन पति शाहजहां अंसारी उम्र 28 वर्ष ग्राम नवडीह थाना कुसमी की रहने वाली थी। वह 9 माह की गर्भवती थी। उसका पहला बच्चा था। 26 फरवारी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे कुसमी अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन महतारी 102 एंबुलेंस से लेकर अंबिकापुर आ रहे थे। पर बरियों के पास एंबुलेंस में ही प्रसव हो गया। परिजन उसे बरियों स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, जहां डॉक्टर ने अंबिकापुर ले जाने को कहा। परिजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जबकि बच्चा स्वस्थ्य है।

हादसे में बाइक सवार नाबालिग की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
शहर के बिलासपुर चौक के पास रविवार की शाम को आमने-सामने दो बाइकों की भिड़ंत में एक नाबालिग गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अनिक सिंह पैकरा पिता श्याम लाल पैकरा उम्र 14 वर्ष लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बटवाही का रहने वाला था। वह रविवार को अपने अन्य दोस्तों के साथ बाइक से अंबिकापुर घूमने आया था। अंबिकापुर बिलासपुर चौक के पास एक अन्य बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में अनिक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जिले में विश्व मलेरिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जिले के शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं विकासखण्डों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम 'Driven to End MalariaÑ Now We Can. Now We Must' रखी गई। इस दौरान बैनर, पाम्पलेट, नारा लेखन, मच्छरदानी उपयोगिता एवं सोर्स रिडक्शन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मलेरिया की जांच एवं उपचार सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध है।

जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन आज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र अम्बिकापुर द्वारा 28 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में विभिन्न निजी नियोजकों द्वारा लगभग 335 पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं।

मोटरसाइकिल,मोबाइल और नगदी चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

करीब 80 हजार का चोरी का माल बरामद

-संवाददाता-
बलरामपुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में सो रहे दंपति के घर से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नगदी चोरी कर फरार हुए आरोपी को राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी गई संपत्ति भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 92/2026 धारा 331(4), 305(1) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, भगवान सिंह पिता शिवलाल,निवासी ग्राम जमापारा थाना लुंड्रा जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) ने थाना राजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जनवरी 2026 से उनके घर पर रिश्तेदार भोला राम काम कर रहा था। दिनांक 21 अप्रैल 2026 की रात लगभग 10 बजे परिवार के सभी सदस्य घर में सो गए थे। तड़के करीब 2:30 बजे उनका पुत्र शौच के लिए उठा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। घर की जांच करने पर पता चला कि अंदर खड़ी दो मोटरसाइकिलों में से एक मोटरसाइकिल क्रमांक CG 30 6989 गायब थी। साथ ही कमरे में रखे 70 हजार नगद, एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन (कीमत लगभग ?10 हजार) और अन्य सामान भी चोरी हो गया था। कुल चोरी गई संपत्ति की कीमत लगभग ?80 हजार आंकी गई। रिपोर्ट पर थाना राजपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर आरोपी भोला राम पिता धीरेन्द्र सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी जमापारा थाना लुंड्रा जिला सरगुजा की तलाश की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसके कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया गया। आरोपी को 27 अप्रैल 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना राजपुर पुलिस टीम के सउनि अशोक तिर्की, प्रधान आरक्षक राजेंद्र ध्रुव, आरक्षक सुखराम कुजूर एवं सैनिक खुशवंत गुप्ता की अहम भूमिका रही।

नारी शक्ति वंदन विधेयक के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन,राहुल गांधी का पुतला दहन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार शाम संकल्प भवन स्थित भाजपा कार्यालय अंबिकापुर में जन आक्रोश महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह तथा प्रदेश प्रभारी दिव्या सिंह सिसोदिया विशेष रूप से उपस्थित रहीं। सम्मेलन के बाद भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शुभांगी बिहाडे के नेतृत्व में स्थानीय घड़ी चौक पर नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक का विरोध करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और इसका विरोध महिलाओं के सम्मान का अपमान है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर सशक्त करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का विरोध महिलाओं के अधिकारों पर प्रहार है। प्रदेश प्रभारी दिव्या सिंह सिसोदिया ने कहा कि जन आक्रोश महिला सम्मेलन के माध्यम से भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। जिला अध्यक्ष शुभांगी बिहाडे ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा संगठन इस विधेयक के समर्थन में एकजुट है और पुतला दहन के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन प्रियंका चौबे एवं नीलू गुप्ता ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला मोर्चा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026... उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर

बीपीएल,घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

-संवाददाता-
बलरामपुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु यह विशेष योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत जिले के निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। 31 मार्च 2023 से पूर्व के निष्क्रिय बीपीएल, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि में राहत दी जाएगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कृषि

श्रेणी के स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शनों के लिए भी मूल राशि में 50 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया पर मूल राशि में 75 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि 1 से 5 वर्ष तक के बकाया पर मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीन किस्तों में भुगतान करने पर मूल राशि में 5 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। छह किस्तों में भुगतान करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना का लाभ लेने हेतु पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण के लिए बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से समय पर योजना का लाभ उठाकर बकाया बिजली बिल का निराकरण कराने की अपील की है।

अपर कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के 9 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत आदेश देकर किया सम्मानित....

-संवाददाता-
जशपुरनगर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शिक्षा विभाग के 9 कर्मचारियों को, जो 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, पेंशन स्वीकृत आदेश (पीपीओ) प्रदान कर शाल-श्रीफल से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी कर्मचारियों के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पूर्व ही पेंशन, अवकाश नकदीकरण एवं अन्य देयकों की प्रक्रिया समय पर पूर्ण कर ली गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

डीजी जेल का केंद्रीय जेल अंबिकापुर में औचक निरीक्षण,व्यवस्थाओं का लिया जायजा...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने 27 अप्रैल को केंद्रीय जेल अंबिकापुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैरक,अस्पताल और पाकशाला का निरीक्षणनिरीक्षण के दौरान डीजी जेल ने बैरक, अस्पताल, उद्योग खंड, पाकशाला और सभा भवन का भ्रमण किया। अस्पताल में बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उद्योग खंड में संचालित बांस, सिलाई और प्रिंटिंग प्रेस इकाइयों के कार्य की उन्होंने सराहना की।

साथ ही प्रिंटिंग प्रेस के उन्नयन के लिए कलर ऑफसेट मशीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। जेल में संचालित 'सरगुजा स्कूल ऑफ आर्ट' में पेंटिंग सीख रहे बंदियों को प्रोत्साहित किया गया। वहीं 'सरगुजा स्कूल ऑफ म्यूजिक' के तहत बंदियों ने संगीतमय प्रस्तुति दी, जिसकी डीजी ने सराहना की। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा बंदियों के कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

पानी के लिए सडक़ों पर उतरे लोग,बाल्टी-डब्बा लेकर निगम कार्यालय का घेराव

अनियमित जल आपूर्ति से बढ़ी परेशानी,टैंकर व्यवस्था की मांग,सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
शहर के कई वार्डों में पेयजल संकट गहराने लगा है। सोमवार को स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर बाल्टी और डब्बा लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि कई वार्डों में नियमित जल आपूर्ति नहीं हो रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। गर्मी बढने के साथ समस्या और गंभीर होती जा रही है,जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि

जिन इलाकों में पानी की कमी ज्यादा है, वहां तत्काल टैंकर के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

साथ ही स्थायी समाधान के लिए खराब पड़ी पाइपलाइन व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने की जरूरत बताई। वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में सुजान बिंद,सुरेश राम बुनकर,अंकुर सिन्हा,संजय ठाकुर, मंगल पांडेय,अनीता साहनी, त्रिभुवन सिंह, अंजली एक्का सहित कई नागरिक मौजूद रहे।

सरगुजा के 406 बूथों पर गूंजा पीएम मोदी का 'मन की बात'

काले हिरण संरक्षण और बांस क्रांति की सराहना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने 406 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 133वें संस्करण का उत्साहपूर्वक श्रवण किया। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में काले हिरण संरक्षण कार्यों की सराहना पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने बांस को घास की श्रेणी में रखने के निर्णय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी बताया। कार्यक्रम के जिला संयोजक जन्मेजय मिश्रा ने बताया कि बूथ स्तरीय आयोजनों में 320 अतिथियों ने ग्रामीणों के साथ कार्यक्रम सुना। इस अवसर पर महापौर मंजूषा भगत सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायालय नज़ूल अधिकारी
सूरजपुर,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 ......

ईश्तहार

आगामी तिथि 30/4/2026

इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता/संस्था/ विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदकगण रामखेलावन आ0 स्व. सुखदेव उम्र 70 वर्ष व अन्य 36 सभी निवासी साहूगली सूरजपुर, थाना व तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा नजूल भूमि पर नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदकगण के पितामह/परपितामह सुमेषर साहू की स्व अर्जित भूमि नजूल प्लाट नम्बर 2093 क्षेत्रफल 0.24 आरे/961 वर्गमीटर एवं प्लाट नम्बर 2094 रकबा 0.06 आरे/283 वर्ग मीटर बाजारपारा स्तर क्रमांक 06 में स्थित है। आवेदकगण एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं, जिनका वषवृक्ष उल्लेख करते हुए आवेदकगण का नाम नजूल अभिलेख में नामांतरित करने का अनुरोध किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 30/4/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 7/4/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

(सील)
नजूल अधिकारी
,सूरजपुर

फायर सीजन को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित,विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण में सक्रिय सहयोग देने की अपील

-संवाददाता-
जशपुरनगर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
जशपुर वनमण्डल में फायर सीजन को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजीवों की सुरक्षा

सुनिश्चित करना है। अभियान के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों की बैठकें आयोजित कर वनाग्नि से होने वाले पर्यावरणीय एवं आर्थिक नुकसान की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीणों से महुआ संग्रहण,तेंदूपत्ता तोड़ाई अथवा खेत सफाई के लिए आग न लगाने की अपील की गई है। वन विभाग ने कहा है कि वन क्षेत्रों में आग लगने की सूचना मिलते ही विभागीय अमला तत्काल मौके पर पहुंचकर नियंत्रण कार्यवाही कर रहा है। नागरिकों से वनों की सुरक्षा में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई है।

8 साल से जमे इंजीनियर,निकाय बना 'निजी प्रोजेक्ट'!

तबादला आदेश फेल,'तिगड़ी सिस्टम' पास-शिवपुर चरचा का हाल बेहाल

- इंजीनियर का राज,कंटीजेंसी का ताज—निकाय में नियम बेअसर
- जहां आदेश हार गया, 'सेटिंग' जीत गई—शिवपुर चरचा पालिका की कहानी
- गिट्टी से गवर्नेंस तक 'सेटिंग', 8 साल से जमे इंजीनियर पर सवाल
- निकाय में तिगड़ी का खेल इंजीनियर,कंटीजेंसी और सीएमओ पर घमासान
- तबादला हुआ कागज पर,इंजीनियर जमे मैदान पर!
- शिवपुर चरचा पालिका : विकास कम,'व्यवस्था' ज्यादा चर्चा में
- नियमों को धता,जुगाड़ को सत्ता—निकाय में अजीब व्यवस्था

-संवाददाता-
कोरिया,29 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

कोरिया जिले के शिवपुर चरचा नगर पालिका में इन दिनों विकास से ज्यादा चर्चा उस 'स्थायित्व मॉडल' की हो रही है, जिसे देखकर प्रबंधन के बड़े-बड़े सिद्धांत भी शरमा जाएं,यहां एक इंजीनियर आठ साल से जमे हुए हैं, दो-दो तबादला आदेशों को ऐसे धता बता चुके हैं जैसे वे सुझाव मात्र हों, और विभाग अंततः 'समझौता' कर बैठा, उनके साथ एक कंटीजेंसी कर्मचारी हैं, जिनका पद भले छोटा हो, लेकिन प्रभाव इतना बड़ा कि हर निर्णय में उनकी मौजूदगी अनिवार्य बताई जाती है, और इस पूरी तिकड़ी के ऊपर हैं सीएमओ, जिन पर आरोप है कि वे सबकुछ जानते हुए भी 'सब ठीक है' की मुद्रा में हैं, व्यंग्य यह कि यहां नियम किताबों में चलते हैं और व्यवस्था 'नेटवर्क' पर।

तबादला आदेश बनाम जमीनी हकीकत: दो आदेश,आठ साल और वही कुर्सी

नगरीय निकायों में स्थानांतरण एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है–कम से कम कागजों में, शिवपुर चरचा में यह प्रक्रिया एक 'केस स्टडी' बन चुकी है, आरोप है कि संबंधित इंजीनियर के दो-दो तबादला आदेश जारी हुए,लेकिन वे आज भी उसी कुर्सी पर विराजमान हैं, सवाल यह नहीं कि आदेश जारी क्यों हुए–सवाल यह है कि लागू क्यों नहीं हुए? क्या आदेश कमजोर थे या इच्छाशक्ति? या फिर 'व्यवस्था' इतनी मजबूत है कि आदेशों को भी इंतजार करना पड़ता है? व्यंग्य में कहा जाए तो यहां तबादला आदेश 'ड्राफ्ट' में रहते हैं और स्थायित्व 'फाइनल' में।

क्रेशर कनेक्शनः गिट्टी में 'गणित' और 'गठजोड़' की चर्चा-

क्रेशर से गिट्टी लेने के कथित दबाव ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, कहा जा रहा है कि संबंधित क्रेशर से 'अच्छी सेटिंग' है, और यही कारण है कि निकाय छोड़ने की इच्छा नहीं बनती, यदि एक ही स्रोत से बार-बार सामग्री ली जाती है, तो गुणवत्ता, कीमत और पारदर्शिता–तीनों पर सवाल उठना स्वाभाविक है, यहां व्यंग्य का तड़का यह है कि सड़कें भले टेढ़ी बनें, लेकिन सप्लाई का रास्ता सीधा और तय रहता है।

राजनीतिक जुगाड़ः हर मौसम में 'फिट' रहने की कला-

इंजीनियर को लेकर एक और दिलचस्प पहलू चर्चा में है की उनकी राजनीतिक पकड़, बताया जाता है कि उन्होंने अलग-अलग दलों के नेतृत्व में काम किया है और हर दौर में अपनी जगह बनाए रखी है, कांग्रेस हो या भाजपा दोनों तरफ 'काम करने का अनुभव' उनके पास है, और 'समन्वय' भी, स्थानीय लोग कहते हैं– 'सरकार बदलती है, सिस्टम बदलता है, लेकिन यहां कुछ लोग नहीं बदलते।' व्यंग्य यह कि यहां पदस्थापना चुनाव से नहीं, 'कनेक्शन' से तय होती है।

इंजीनियर का 'एक्सटेंडेड रोल': तकनीक से ट्रेड तक- इंजीनियर का काम तकनीकी स्वीकृतियां देना, गुणवत्ता देखना और कार्यों की निगरानी करना होता है,लेकिन शिवपुर चरचा में आरोप है कि यह भूमिका 'एक्सटेंडेड' हो चुकी है अब इसमें सप्लाई मैनेजमेंट भी शामिल है,स्थानीय सूत्र बताते हैं कि ठेकेदारों को एक विशेष क्रेशर से गिट्टी लेने के लिए कहा जाता है, अगर यह सही है, तो यह केवल सलाह नहीं, बल्कि 'अनिवार्य विकल्प' जैसा बन जाता है, अब सवाल उठता है क्या यह तकनीकी निर्णय है या आर्थिक? और अगर सप्लाई का रास्ता तय है, तो प्रतिस्पर्धा कहां गई? व्यंग्य यह कि यहां टेंडर कम और 'ट्रेंड' ज्यादा चलता है जहां सामग्री का रास्ता पहले से तय रहता है।

कंटीजेंसी कर्मचारीः पद छोटा,प्रभाव बड़ा- इस पूरे मामले में सबसे रोचक किरदार है कंटीजेंसी कर्मचारी, मानदेय सीमित, पद अस्थायी, लेकिन प्रभाव स्थायी और व्यापक, बताया जाता है कि हर निर्णय में उनकी उपस्थिति रहती है, और उन्हें निकाय का 'सबसे विश्वस्त' माना जाता है, अब सवाल यह है कि यह विश्वास कैसे बना? क्या यह अनुभव का परिणाम है या 'एक्सेस' का? व्यंग्य यह कि यहां कंटीजेंसी कर्मचारी 'कंट्रोल रूम' बन गया है जहां से फैसलों की दिशा तय होती है।

सीएमओ की भूमिका : स्थानीय होने का 'लाभ' या 'लापरवाही'?- सीएमओ इस पूरी कहानी का तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, आरोप है कि गृह जिले में पदस्थ होने के कारण वे निश्चिंत हैं और अनियमितताओं के बावजूद सख्त रुख नहीं अपनाते,स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि 'दिखावा ज्यादा,कार्रवाई कम' नजर आती है,अब सवाल यह है क्या स्थानीय होना प्रशासनिक ताकत बन गया है? या फिर यह निष्पक्षता में बाधा बन रहा है? व्यंग्य यह कि यहां निगरानी 'लोकल' है और जवाबदेही 'ग्लोबल' हो गई है–कहीं भी फिट नहीं बैठती।

निर्माण कार्यों पर सवाल : गुणवत्ता बनाम 'व्यवस्था'

नगर पालिका में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं, लोग कहते हैं कि काम होता तो दिखता है,लेकिन टिकता नहीं, सामग्री की गुणवत्ता, लागत और क्रियान्वयन–तीनों पर सवाल हैं,यदि सप्लाई और स्वीकृति एक ही प्रभाव में हों, तो गुणवत्ता पर असर पड़ना तय है,व्यंग्य में कहें तो–'काम जल्दी होता है,ताकि दोबारा जल्दी हो सके।'

तिगड़ी का 'मैनेजमेंट मॉडल': जिम्मेदारी किसकी?

इंजीनियर,कंटीजेंसी कर्मचारी और सीएमओ तीनों मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते नजर आते हैं, जिसे स्थानीय लोग 'तिगड़ी' कहते हैं,अब इस तिगड़ी में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि निर्णय सामूहिक हैं,लेकिन जवाबदेही व्यक्तिगत नहीं,यहां सबसे बड़ा सवाल यही है जब सब मिलकर काम करते हैं,तो जवाब कौन देगा?

विभागीय आदेशों की स्थितिः पालन या प्रतीक्षा?

तबादला आदेशों का लागू न होना इस बात का संकेत है कि विभागीय आदेशों की प्रभावशीलता पर सवाल हैं,यदि आदेश जारी होने के बाद भी स्थिति नहीं बदलती, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं 'पालन' की प्रक्रिया कमजोर है, व्यंग्य यह कि यहां आदेश आते हैं, रजिस्टर में दर्ज होते हैं और फिर 'समय के साथ समायोजित' हो जाते हैं।

जांच की मांग : पारदर्शिता ही समाधान

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जरूरत है—निष्पक्ष जांच, यदि आरोप सही हैं, तो कार्रवाई जरूरी है, और यदि गलत हैं,तो स्पष्टता जरूरी है, पारदर्शिता ही वह रास्ता है,जिससे व्यवस्था पर भरोसा वापस आ सकता है।

विकास होगा या 'व्यवस्था' ही चलेगी?

शिवपुर चरचा नगर पालिका का यह मामला केवल एक निकाय की कहानी नहीं है, बल्कि उस प्रवृत्ति का उदाहरण है जहां नियमों से ज्यादा 'जुगाड़' प्रभावी दिखता है,आठ साल का स्थायित्व, दो तबादला आदेशों की अनदेखी, सप्लाई पर सवाल और तिगड़ी का प्रभाव-ये सब मिलकर एक ऐसा चित्र बनाते हैं, जो चिंताजनक भी है और व्यंग्यात्मक भी, अब देखना यह है कि क्या इस मामले में वास्तविक सुधार होता है या फिर सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं बदली, तो विकास की परिभाषा भी 'समायोजित' होती रहेगी। और अंत में एक सवाल- यहां काम चल रहा है,या सिस्टम चलाया जा रहा है?

गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांगः सूरजपुर में गौसेवकों का हस्ताक्षर अभियान, सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
सूरजपुर 27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर तहसील में गौसेवकों द्वारा गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत व्यापक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, इस अभियान के माध्यम से देशभर में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने तथा गो सेवा के लिए ठोस कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग उठाई गई।,अभियान के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सूरजपुर को सौंपा गया।

देशव्यापी अभियान के तहत सूरजपुर में पहल

बताया गया कि यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे गो सम्मान आह्वान अभियान का हिस्सा है, इसी क्रम में सूरजपुर तहसील के गौसेवकों ने भी स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क कर हस्ताक्षर जुटाए और अपनी मांगों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया।

प्रमुख मांगें रखीं गई

ज्ञापन में गौसेवकों द्वारा कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल की गई हैं देशभर में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाए,गौमाता को राष्ट्र स्तर पर सम्मानित दर्जा (राष्ट्रमाता) दिया जाए,गो सेवा के लिए केंद्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाया जाए,गो संरक्षण और संवर्धन के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया जाए।

तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन

हस्ताक्षर अभियान पूर्ण होने के बाद गौसेवकों ने एकत्रित हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन तहसीलदार सूरजपुर को सौंपा,इस ज्ञापन के माध्यम से उनकी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया गया।

बड़ी संख्या में गौसेवक रहे उपस्थित

इस कार्यक्रम में सूरजपुर तहसील के बड़ी संख्या में गौसेवक शामिल हुए, सभी ने एकजुट होकर अभियान को सफल बनाने और गौ संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।

कोरिया के सलबा गांव में 'जल-युद्ध', प्यास बुझाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे ग्रामीण

राजन पाण्डेय

कोरिया,27 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

कहते हैं 'जल ही जीवन है', लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सलबा के लिए जल अब 'काल' बनता जा रहा है। आजादी के सात दशकों बाद भी यहाँ की तस्वीरें विकास के दावों के गाल पर एक कड़ा तमाचा हैं। भीषण गर्मी की दस्तक के साथ ही इस गाँव में पानी की एक-एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है, और प्रशासन की चुप्पी ग्रामीणों की मुश्किलों को और बढ़ा रही है।

नरक जैसी स्थिति : गंदे पानी से बुझ रही प्यास-सलबा के ग्रामीण आज उस दौर में जीने को विवश हैं, जिसकी कल्पना भी आधुनिक समाज में डरावनी लगती है। गाँव के लोग अपनी और अपने मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए एक पुरानी 'ढोढ़ी' (झरिया या छोटा गड्ढा) पर निर्भर हैं। इस ढोढ़ी का पानी न केवल मटमैला और दूषित है, बल्कि इसमें नग्न आंखों से कीड़े और छोटे जीव तैरते देखे जा सकते हैं। डॉक्टर जिस पानी को छूने तक से मना करते हैं, उसी पानी को छानकर पीना यहाँ के बच्चों और बुजुर्गों की मजबूरी बन गई है। यह स्थिति किसी भी वक्त गाँव में बड़ी महामारी को निमंत्रण दे सकती है।

नल-जल योजना : शोपीस बने नल,सूखी पड़ी पाइपलाइन- प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' योजना का हश्र यहाँ के गलियों में देखा जा सकता है, गाँव के हर घर के सामने शान से नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन वे सिर्फ 'शोपीस' बनकर रह गए हैं, धरातल पर न तो पानी की टंकी का निर्माण हुआ है और न ही पाइपलाइन में पानी की एक बूंद पहुंची है,सरकार के रिकॉर्ड में शायद यह गाँव 'नल-युक्त' हो चुका हो, लेकिन हकीकत में यहाँ की महिलाएं आज भी मीलों का सफर तय कर दूषित पानी ढोने को मजबूर हैं, गाँव के हैंडपंप भी सफेद हाथी साबित हो रहे हैं; आधे सूखे पड़े हैं और बाकियों से उगल रहा गंदा पानी पीने लायक नहीं है।

प्रशासनिक लाचारीः 'ड्राय' बोर और गिरता जलस्तर- जब इस समस्या को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सवाल किया जाता है, तो जवाब में सिर्फ 'तकनीकी मजबूरियां' गिनाई जाती हैं, ग्राम सरपंच आशु कुजूर का कहना है कि उन्होंने प्रयास तो किए, लेकिन जलस्तर का लगातार नीचे जाना सबसे बड़ी बाधा है, हाल ही में पीएचई विभाग द्वारा कराए गए बोर खनन में सफलता नहीं मिली क्योंकि जमीन के नीचे पानी नहीं मिला, विभाग का तर्क है कि जब तक कोई मजबूत जल स्रोत नहीं मिलता, तब तक नल-जल योजना का ढांचा खड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इस 'तकनीकी खोज' के बीच ग्रामीण कब तक प्यासे रहेंगे?

एक मानवीय त्रासदी की आहट- ग्रामीण लालसाय और अनिल बेग ने बताया कि जैसे-जैसे पारा चढ़ेगा, यह ढोढ़ी भी सूख जाएगी, इसके बाद गाँव के पास पलायन करने या बूंद-बूंद को तरसकर दम तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, ग्रामीणों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि जिला मुख्यालय के इतने करीब होने के बावजूद अधिकारी यहाँ का दौरा करने और कोई वैकल्पिक व्यवस्था (जैसे टैंकर या गहरा खनन) करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं।

खौफ का सायाः पानी के स्रोत पर मधुमक्खियों का पहरा-

पानी के लिए संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। कुदरत और सिस्टम की मार के बीच अब 'मधुमक्खियों' का कहर टूट पड़ा है, पानी के इसी एकमात्र स्रोत के ठीक ऊपर और आसपास मधुमक्खियों ने बड़े-बड़े छत्ते बना लिए हैं, ग्रामीण जब पानी भरने या नहाने जाते हैं, तो मधुमक्खियां उन पर प्राणघातक हमला कर देती हैं, स्थानीय महिला फूलमती बेग की आंखों में दहशत साफ दिखती है, वे कहती हैं– 'अभी कुछ दिन पहले ही एक छोटे बच्चे पर मधुमक्खियों ने बुरी तरह हमला कर दिया था। तब से बच्चे वहां जाने के नाम से ही कांपने लगते हैं, हमें प्यास बुझाने जाना है या अपनी जान बचानी है, समझ नहीं आता।'

प्रशासन से सीधे सवाल

- क्या प्रशासन को किसी बड़ी अनहोनी या बच्चे की जान जाने का इंतजार है?
- मुख्यालय से 8 किमी दूर की यह दुर्दशा है, तो दूरस्थ वनांचलों का क्या हाल होगा?
- 'जल जीवन मिशन' के अधूरे काम के लिए ठेकेदारों और जिम्मेदार इंजीनियरों पर कार्रवाई कब होगी?

इनका कहना है...

गंदा हो या अच्छा यही पानी सहारा है. कुछ दिन पहले एक छोटा बच्चे पर भी मधुमक्खियों ने हमला किया। इसके बाद से बच्चे यहां जाने से डरने लगे हैं।

स्थानीय महिला फूलमती बेग

हमने पीएचई विभाग के माध्यम से बोर खनन भी कराया लेकिन वहां ड्राई बोर निकल गया। जलस्तर कम होने की वजह से अब आगे खनन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है।

आशु कुजूर,सरपंच

गन्ना किसानों और मजदूरों के बकाया पर बवाल,केरता शक्कर कारखाने में तालाबंदी

-संवाददाता-
सूरजपुर,27 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

प्रतापपुर स्थित केरता शक्कर कारखाने में गन्ना किसानों और मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है,लंबे समय से भुगतान नहीं होने और प्रबंधन की लापरवाही से नाराज किसानों और मजदूरों ने सोमवार को कारखाने में तालाबंदी कर दी,इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है।

बकाया भुगतान को लेकर बढ़ा आक्रोश-किसानों और मजदूरों का कहना है कि वे काफी समय से अपने बकाया भुगतान की मांग कर रहे थे,कई बार प्रबंधन से बातचीत और ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, लगातार अनदेखी से नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित लोगों ने कारखाने के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

कांग्रेस का समर्थन,शशि सिंह मौके पर पहुंचीं-प्रदर्शन को जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर की अध्यक्ष शशि सिंह का समर्थन मिला। वे स्वयं मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया,उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों का बकाया रोकना गंभीर मामला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की बात कही गई।

कारखाने का कामकाज ठप- तालाबंदी के कारण शक्कर कारखाने का संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया है, कर्मचारियों और अधिकारियों की आवाजाही भी बाधित हुई है, स्थानीय स्तर पर इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

प्रबंधन पर लगाए गए आरोप- प्रदर्शनकारियों ने कारखाना प्रबंधन पर कई आरोप लगाए हैं गन्ना किसानों का भुगतान लंबित, मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं, शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए।

बड़ी संख्या में लोग रहे शामिल- आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए,इस दौरान विमलेश तिवारी, विद्यासागर सिंह,अनिल गुप्ता,सुरेश आयाम, त्रिभुवन सिंह, नवीन जायसवाल, डी. राम,रोहन राजवाड़े, बबीता गुप्ता,सतवंत सिंह,अविनाश साहू, लिवनेश सिंह,दिनेश राजवाड़े,गोल्डी खान,सुरेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।

करोड़ों का काला सोना, प्यासा कटगोड़ी का कोना-कोना

आखिर सामाजिक सरोकार क्यों भूला एसईसीएल ?

सीएसआर से क्षेत्र के विकास कार्यों को नजरअंदाज कर रहा एसईसीएल प्रबंधन

चरचा आर ओ माइन के कटगोड़ी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर नही है...प्रबंधन का ध्यान

राजन पाण्डेय

कोरिया/सोनहत,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। एसईसीएल की कोयला खदानों से सरकार को कई हजार करोड़ रूपये का रायल्टी प्रतिवर्ष मिलता हैं, कोरिया जिले के ही बैकुण्ठपुर,चरचा,चिरमिरी हसदेव,कटकोना, पण्डोवपारा व झिलमिली सहित अनेक कोयला खदानों से भी भरपूर राजस्व शासन को मिलता हैं, करोडों टन कोयला उत्पादन कर एसईसीएल भी कई करोड़ रूपए प्रतिवर्ष लाभ कमाती हैं, करोडों रूपए की आमदनी होने के बावजूद एसईसीएल द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए विकास कार्यों की नजर अंदाजी लगातार की जा रही हैं, एसईसीएल के आस - पास के इलाकों में हमेशा बदहाल नजर आते हैं, कोयले की उड़ने वाली डस्ट से जहां लोगों के बीमार होने की संभावना निरन्तर बनी रहती है वहीं लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानी होती हैं। उल्लेखनीय है की सोनहत विकासखंड का कटगोड़ी क्षेत्र जो की चरचा आर ओ माईन के अंर्तगत आता है जहां से एसईसीएल ने करोड़ों रूपय का मुनाफा कमाया हैं, इसके बावजूद क्षेत्र के लोग बुनियाद सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, सडकें जर्जर हैं पेयजल की समस्या वर्षों से बनी हुई हैं, जो गर्मी आते ही विकराल रूप धारण कर लेती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी कमी का अभाव निरन्तर बना रहता हैं, शासन के नियमानुसार कोयला उत्पादन करने वाली कम्पनी एसईसीएल खदान क्षेत्र के 10-15 किमी के दायरे में आने वाले गांवों व शहर का विकास करने के लिए कटिबद्ध हैं, इसके बावजूद गांवों में एसईसीएल के माध्यम से बुनियादी सुविधाए उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जबकि सामुदायिक विकास मद (सीएसआर) में एसईसीएल द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रूपए खर्च किए जाने का दावा किया जाता हैं, इसके बाद भी इन क्षेत्रों में बुनियादी समस्याए दूर नहीं हो रही हैं।

मनोरंजन व सौन्दर्यीकरण के नाम पर शून्य-

क्षेत्र में एसईसीएल द्वारा शहरों के सौन्दयीकरण व स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए गए है, कलेक्टर कोरिया की पहल पर सीएसआर मद से एसईसीएल द्वारा झुमका वोट क्लब का निर्माण कराया गया था, उसी वक्त कटगोड़ी वासीयों को भी उम्मीद जगी थी की शायद कटगोड़ी क्षेत्र में भी विकास कार्य कराए जावेंगे लेकिन कटगोड़ी क्षेत्र एक बार फिर उपेक्षित हो गया वर्तमान समय में आलम की कटगोड़ी के कई मार्ग कच्चे हैं और क्षतिग्रस्त है लेकिन एस ई सी एल प्रबंधन के द्वारा क्षेत्र स्तर पर विकास कार्य नही कराए जाने से ग्राम वासीयों में मायूसी छाई हुई है।

यह कार्य होने हैं सीएसआर मद में- सीएसआर मद में बुनियाद परियोजना के अन्तर्गत कोयला कम्पनी को गांवों में बुनियादी सुविधाए उपलब्ध कराने के साथ खदान एरिया के 15किमी के दायरे में सड़क, बिजली, व पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के साथ गांव में स्वच्छता में सुधार कार्य कराना हैं, अरमान की परियोजना के अन्तर्गत आस - पास के इलाकों में शिक्षा की गुणवक्ता में सुधार लाना कम्प्यूटर शिक्षा को बढावा देना बैगा जैसे विशेष समुदाय के बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान कराना हैं, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य ग्राम के अन्तर्गत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी कोयला कम्पनी की हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो इन तीनों परियोजनाओं में से किसी भी मामले में एसईसीएल ने क्षेत्र में गंभीरता से कोई कार्य नहीं किया हैं, कम्पनी केवल औपचारिकता निभाने तक रह गई हैं।

खनन से जल स्तर में भारी गिरावट

कटगोड़ी में भूमिगत कोल खनन से जल स्तर में भारी गिरावट है आलम है कि कई हैंड पम्प सिर्फ हवा उगल रहे हैं,बोर में भी सही ढंग से पानी नही आ रहा है जिससे ग्राम वासियों को भारी परेशानी है, पिछ्ले वर्षों में तो ब्लास्टिंग की समस्या ने भी परेशान कर रखा था प्रबंधन द्वारा खनन के दौरान की जाने वाली ब्लास्टिंग से कई घरों की दीवार क्रेक हो गई है लोगो को भूकम्प जैसे झटके भी महसूस होते थे।

प्यासा कटगोड़ी:'हवा' उगलते हैंडपंप- भूमिगत खनन ने क्षेत्र के जलस्तर को पाताल में भेज दिया है, ग्रामीण बताते हैं कि पिछ्ले कई वर्षों से पेयजल की समस्या विकराल है। प्रबंधन चंद टैंकर भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन लोगो का कहना है कि इस वर्ष एसईसीएल के टैंकर भी नसीब नही हो पा रहे हैं जबकि स्थायी पाइपलाइन योजना आज भी फाइलों में धूल फांक रही है।

ब्लास्टिंग का खौफ : दरकती दीवारें, कांपती रूह- खनन के दौरान होने वाली भारी ब्लास्टिंग ने ग्रामीणों के आशियानों को खंडहर में तब्दील कर दिया है, लोगों के घरों की दीवारों में आई दरारें एसईसीएल की संवेदनहीनता की गवाही दे रही हैं। यहाँ लोग घर में रहते हुए भी 'भूकंप' के साये में जीते हैं।

क्या कहते है लोग...

कटगोड़ी क्षेत्र से करोड़ों कमाने के बावजूद एसईसीएल द्वारा विकास कार्य नही कराया जा रहा है। जबकी इस संबंध में कई बार एसईसीएल प्रबंधन से मांग की जा चुकी है।

नीलेश साहू कटगोड़ी

एसईसीएल प्रबंधन क्षेत्र से करोडों की आमदनी कर रहा है, कटगोड़ी क्षेत्र में पानी एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को दूर कराने पिछले कई वर्ष में चक्काजाम एवं आंदोलन कर ज्ञापन दिया गया था जिस पर समस्या दूर करने को लेकर आश्वासन भी मिला था लेकिन आज तक चंद टैंकर पानी और कुछ स्ट्रीट लाइट के अलावा कुछ भी नहीं मिला, प्रबंधन से पुन: मांग की जावेगी

जय चंद सोनपाकर अधिवक्ता

एसईसीएल को विकास कार्य कराना होगा खास कर स्वस्थ्य सुविधाओ के क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक उपकरण एवं आधुनिक मशीनें प्रबंधन के तरफ से मिलनी चाहिए पानी के लिए एसईसीएल के सौजन्य से कटगोड़ी क्षेत्र में बड़ा प्रोजेक्ट लगना चाहिए जो हमेशा के लिए काम आए पर प्रबंधन के ध्यान नही देने से बुनियादी सुविधाओं का आभाव बना हुआ है।

रुद्र साहू कटगोड़ी

कॉर्पोरेट लूट या 'सामाजिक विकास-

झुमका वोट क्लब जैसे सौंदर्यीकरण के कार्यों पर पैसे देने वाला प्रबंधन अपने प्रभावित ग्रामीणों को साफ पानी क्यों नहीं दे पा रहा? कटगोड़ी क्षेत्र की जनता पूछ रही है कि हमारा हक कहाँ है जीएम साहब....

मनेंद्रगढ़ में जुए पर कार्रवाई या सिर्फ औपचारिकता? छोटे खिलाड़ी गिरफ्तार, बड़े गायब

छोटे फड़ पर कार्रवाई, बड़े जुआ नेटवर्क पर चुप्पी-सवालों के घेरे में पुलिस

खबर के बाद दिखी 'सख्ती', लेकिन बड़े जुआ अड्डे अब भी सुरक्षित?

छोटे जुआरियों पर शिकंजा,बड़े नेटवर्क को संरक्षण? पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

घुटरा जंगल में रेड,5 गिरफ्तार – लेकिन बड़े जुआ सिंडिकेट पर अब भी सन्नाटा

खबर में पहले ही हुआ था खुलासा,अब कार्रवाई ने उठाए नए सवाल

दोहरी रणनीति का आरोप – छोटे फड़ पर दबिश, बड़े नेटवर्क पर नहीं पहुंची पुलिस

57 हजार की जब्ती,लेकिन बड़े खेल पर कोई असर नहीं

-संवाददाता-
मनेंद्रगढ़,27 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़ जिले में जुए के खिलाफ पुलिस की हालिया कार्रवाई ने जितने सवालों के जवाब दिए हैं, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए हैं, दैनिक घटती घटना द्वारा हाल ही में प्रकाशित खबर में जिस 'दोहरी व्यवस्था' और 'सेटिंग आधारित जुआ नेटवर्क' का जिक्र किया गया था, ताजा घटनाक्रम ने उसे और मजबूत कर दिया है,खबर में साफ तौर पर संकेत दिया गया था कि जिले में जुआ दो स्तरों पर संचालित हो रहा था एक छोटा,आसानी से पकड़ा जाने वाला फड़ और दूसरा बड़ा,संगठित और कथित तौर पर संरक्षण प्राप्त नेटवर्क,अब पुलिस की कार्रवाई ठीक उसी छोटे फड़ तक सीमित दिखाई दे रही है, जिससे पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

घुटरा सलवा जंगल में छापा में 5 जुआरी गिरफ्तार

27 अप्रैल को मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घुटरा-सलवा जंगल में रेड कार्रवाई की, यह स्थान मुख्य मार्ग से लगभग एक किलोमीटर अंदर बताया गया, जहां लंबे समय से जुआ खेलने की सूचनाएं मिल रही थीं,पुलिस टीम ने इस बार रणनीति बदलते हुए ग्रामीण वेशभूषा में मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, ताकि जुआरियों को शक न हो, जैसे ही टीम ने दबिश दी, वहां मौजूद लोगों को पकड़ लिया गया, इस कार्रवाई में कुल 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया,जिनकी पहचान इस प्रकार है संतोष कुमार सांडिल्य (32 वर्ष), निवेश कुमार खलखो (19 वर्ष), भानु सिंह गोंड (36 वर्ष), विवेक मिश्रा (27 वर्ष), दिलीप कुमार (26 वर्ष) ये सभी अलग-अलग इलाकों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि जुए का नेटवर्क केवल एक गांव तक सीमित नहीं है।

जब्ती की कहानी सीमित रकम,सीमित दायरा

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 57,000 नगद, 4 ताश की गड्डियां,1 तिरपाल जब्त किए हैं, इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, हालांकि जब्ती की यह राशि और सामग्री इस बात की ओर इशारा करती है कि यह कोई बड़ा या संगठित जुआ अड्डा नहीं था, बल्कि एक सीमित स्तर का फड़ था।

बड़े जुआ नेटवर्क पर सवाल बरकरार

स्थानीय सूत्रों और जानकारों का कहना है कि जिले में लंबे समय से बड़े स्तर पर जुआ संचालित हो रहा है, इसमें बाहरी जिलों और राज्यों के लोग भी शामिल रहते हैं, नेटवर्क लगातार अपनी लोकेशन बदलता है, सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि बड़े अड्डों तक पहुंच पाना आसान नहीं होता इसके बावजूद अब तक किसी बड़े जुआ अड्डे पर ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, यही कारण है कि यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या पुलिस को बड़े नेटवर्क की जानकारी नहीं है? या फिर जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही?

पुलिस का दावा लगातार चल रहे अभियान

पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आईजी सरगुजा रेंज और एसपी एमसीबी के निर्देश पर जुआ-सट्टा के खिलाफ अभियान चल रहा है, कोतवाली थाना और साइबर सेल की टीम लगातार सक्रिय है, मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचनाएं जुटाई जा रही हैं, आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

खबर का असर या पहले से तय पटकथा?

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह है कि यह कार्रवाई ठीक उस खबर के बाद हुई, जिसमें जुए के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया था, खबर में पहले ही यह दावा किया गया था कि जुआ दो अलग-अलग जगहों पर चल रहा है, छोटे फड़ पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, बड़े नेटवर्क को संरक्षण प्राप्त है, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं, अब जो कार्रवाई सामने आई है, वह इन दावों से मेल खाती नजर आ रही है। यही वजह है कि लोग इसे 'खबर के दबाव में की गई औपचारिक कार्रवाई' के तौर पर देख रहे हैं।

जमीनी सच्चाई ये है की छोटे पर कार्रवाई,बड़े पर चुप्पी

लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीर उभर रही है, वह पुलिस के दावों से मेल नहीं खाती, कार्रवाई केवल छोटे फड़ तक सीमित, सीमित संख्या में गिरफ्तारियां, बड़े नेटवर्क पर कोई असर नहीं, यह स्थिति यह संकेत देती है कि या तो पुलिस की रणनीति अधूरी है, या फिर कार्रवाई चयनात्मक तरीके से की जा रही है।

विश्वसनीयता का संकट

इस तरह की कार्रवाइयों से सबसे बड़ा नुकसान पुलिस की विश्वसनीयता को होता है,जब जनता को यह महसूस होने लगता है कि बड़े अपराधी बच रहे हैं, छोटे लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है तो कानून व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है।

क्या आगे होगी बड़ी कार्रवाई? अब पूरा मामला इस बात पर टिका है कि...

- क्या पुलिस आने वाले समय में बड़े जुआ नेटवर्क पर कार्रवाई करेगी?
- क्या इस नेटवर्क के पीछे मौजूद असली संचालकों तक पहुंच बनाई जाएगी?
- या फिर कार्रवाई का दायरा यहीं तक सीमित रहेगा?

असली परीक्षा अभी बाकी...

घुटरा जंगल में हुई यह कार्रवाई अपने आप में एक कदम जरूर है,लेकिन इसे निर्णायक नहीं कहा जा सकता, जब तक बड़े और संगठित जुआ नेटवर्क पर ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती,तब तक ऐसे छापे केवल 'दिखावटी सख्ती' के रूप में ही देखे जाएंगे, मनेंद्रगढ़ में जुए के खिलाफ असली लड़ाई अभी बाकी है-और इस लड़ाई में पुलिस की नीयत, रणनीति और पारदर्शिता ही उसकी सफलता तय करेगी।

एक ही तारीख,एक ही उम्र और एक ही मौत का कारण बॉलीवुड के दो जिगरी यार के निधन पर रोया था पूरा देश

बॉलीवुड के दो कमाल के स्टार्स,जो जिगरी यार थे। लेकन उनकी दोस्ती सिर्फ सिनेमा ही नहीं बल्कि मौत तक उनके साथ रही। इत्तेफाक ऐसी चीज है जो कुछ बेहतरीन यादें देकर जाती हैं लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसे भी होते हैं जो हैरान भी करते हैं और दुखी भी। एक ऐसा ही इत्तेफाक हुआ बॉलीवुड के दो जिगरी यारों के बीच। फिरोज खान और विनोद खन्ना- दोनों का निधन एक ही तारीख पर हुआ, इतना ही नहीं निधन के वक्त दोनों की उम्र भी उतनी ही थी और उनके निधन का कारण भी एक ही था।

जिगरी यारों की एक ही दिन हुई मौत

अपनी पीढ़ी के सबसे आकर्षक अभिनेताओं में से एक, विनोद खन्ना का निधन उसी तारीख को हुआ, जिस तारीख को आठ साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में उनके सबसे करीबी दोस्त फिरोज खान का निधन हुआ था। अपनी मृत्यु के समय दोनों की उम्र एक समान थी और दोनों ही एक ही बीमारी कैंसर से पीड़ित थे। विनोद खन्ना और फिरोज खान का निधन 70 की उम्र में 27 अप्रैल को हुआ था।

कई फिल्मों में किया साथ में काम

विनोद और फिरोज ने अपनी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक, कुर्बानी (1980) में दोस्तों की भूमिका निभाई थी, और उसके बाद दयावान (1988) में साथ काम किया; यह मणिरत्नम की कल्ट तमिल क्लासिक फिल्म नायकन का रीमेक थी। लेकिन उनकी दोस्ती इन फिल्मों से भी पहले की थी। उनकी गहरी दोस्ती तब हुई थी, जब उन्होंने अपनी पहली हिट फिल्म शंकर शंभू (1976) में साथ काम किया था; इस फिल्म का निर्देशन चांद ने किया था।

विनोद के बुरे वक्त में फिरोज खान ने दिया था साथ

जब विनोद,अमिताभ बच्चन के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय अभिनेता थे,तब उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया। वह एक माली बन गए और,जैसा कि उन्होंने उन दिनों एक इंटरव्यू में कहा था, दुनिया को अपने हाल पर चलने देने में ही खुश थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका में ओशो के आश्रम से जुड़े विवादों के बाद, विनोद को एक नाटकीय अंदाज में अपनी दूसरी पारी के लिए फिल्मों की दुनिया में वापस लौटना पड़ा। फिरोज उन शुरुआती प्रोड्यूसर्स में से एक थे,जिन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत किया और उन्हें दयावान के लिए साइन किया; हालांकि, मुकुल आनंद की इंसाफ (1986) और राज एन. सिप्पी की सत्यमेव जयते (1986) उनकी वापसी की पहली दो फिल्में थीं।

आठ साल के अंतर में दोनों का हुआ था निधन

फिरोज की फेफड़ों के कैंसर से मौत होने तक वे जिंदगी भर दोस्त बने रहे। फिरोज के गुजरने से कुछ दिन पहले, विनोद, धर्मेंद्र के साथ मुंबई के उस अस्पताल में उनसे मिलने गए थे जहां वे भर्ती थे। वहां वे दोनों मिलकर फूट-फूटकर रोए। विडंबना यह है कि आठ साल बाद, जब विनोद को ब्लैडर कैंसर का पता चला, तो क्रूर किस्मत ने उन्हें भी उसी जगह पहुंचा दिया। 27 अप्रैल को जो उनके सबसे करीबी दोस्त की आठवीं पुण्यतिथि थी, विनोद अपने परिवार, दोस्तों और लाखों फैंस को शोक में डूबा छोड़कर इस दुनिया से चले गए।

आखिरकार विजय की फिल्म को मिली हरी झंडी

सेंसर बोर्ड के साथ लंबी लड़ाई के बाद, थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म जन नायकन की नई रिलीज डेट तय हो गई है।थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म, जन नायकन, आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। सेंसर बोर्ड के साथ लंबी लड़ाई के बाद, इस फिल्म की रिलीज की तारीख तय हो गई है। आइए जानते हैं पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा कब रिलीज होगी?

लीक होने के बाद मेकर्स को अब मिली राहत

केव्हीएन प्रोडक्शंस द्वारा बनाई गई फिल्म जन नायकन कुछ दिन पहले ऑनलाइन लीक हो गई थी, जिससे निश्चित रूप से इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ेगा; हालांकि, थलापति विजय की स्टार पावर इतनी है कि यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग हासिल कर सकती है।

कब रिलीज होगी पॉलिटिकल थ्रिलर?

पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म 8 मई, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। यह फिल्म तमिलनाडु चुनावों के नतीजों के बाद रिलीज होगी। विजय और उनकी पार्टी के लिए चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं, यह भी एक अहम फैक्टर होगा जो तय करेगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी। जना नायकन का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है। इस फिल्म में विजय लीड एक्टर है वहीं बॉबी देओल मुख्य विलेन और पूजा हेगड़े फीमेल लीड का किरदार निभाएंगी। मुख्य कलाकारों के अलावा, इस फिल्म में मामिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, प्रियमणि, नारायण और कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।यह फिल्म पहले 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि सेंसर से जुड़ी दिक्कतों के चलते इसकी रिलीज डेट टालनी पड़ी।

करोड़ों का मालिक बना महाभारत का अभिमन्यु

एक्टिंग छोड़कर छाप रहा मोटा पैसा, जीता है लग्जरी लाइफ

निर्देशक बी आर चोपड़ा की महाभारत में अभिमन्यु का किरदार निभाने वाला एक्टर आज बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। 80 के दशक में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला माइथोलॉजिकल शो महाभारत हर किसी का फेवरेट माना जाता था। इस शो की कास्ट के बारे में आज भी बात की जाती है, जिसके आधार पर भीष्म पितामह और अर्जुन जैसे कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स के बारे में चर्चा की जाती है। इस बीच हम आपको महाभारत में अभिमन्यु का किरदार निभाने वाले एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज करोड़ों का बिजनेस चला रहा है और लग्जरी लाइफ जी रहा है।

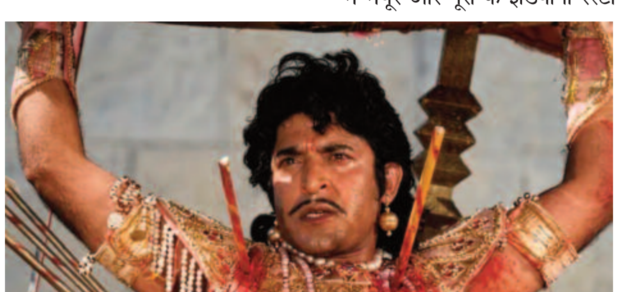

महाभारत का अभिमन्यु बना करोड़पति

करीब 4 दशक पहले टेलीकास्ट होने वाली महाभारत में एक्टर मयूर राज वर्मा ने अभिमन्यु की भूमिका को अदा किया था। मयूर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी इंडस्ट्री में काफी फेमस हुए। लेकिन उनको सबसे अधिक लोकप्रियता बी आर चोपड़ा की महाभारत में अभिमन्यु का किरदार निभाने से मिली। मौजूदा समय में मयूर अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में रहते हैं। एक्टिंग से नाता तोड़ने के बाद मयूर ने विदेशी सरजमीं पर रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू किया, जिसका नाम इंडियाना रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट को मयूर अपनी पत्नी नूरी के साथ मिलकर चलाते हैं। आज के समय में मयूर और नूरी के इंडियाना रेस्टोरेंट का सालाना टर्नओवर करोड़ों में होता है। इस आधार पर महाभारत से पहचान बनाने वाले मयूर फिलहाल करोड़पति बन गए हैं और विदेशी में अपने परिवार संग खुशहाल जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। इस तरह से मयूर राज वर्मा खूब पैसा कमाते हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर विदेश में धाक जमाए हुए हैं। बता दें कि मयूर और नूरी के दो बच्चे भी हैं, जो इंग्लैंड में पढ़ाई करते हैं।

बिग बी की वजह से हुए लोकप्रिय

सिर्फ महाभारत ही नहीं बल्कि बतौर बाल कलाकार मयूर राज वर्मा ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। 70 से लेकर 80 के दशक बीच वह मास्टर मयूर के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में उनके बचपन की भूमिका को अदा किया। अमिताभ बच्चन के अलावा मयूर राज वर्मा दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र और दिलीप कुमार के बचपन का किरदार भी निभा चुके हैं।

निमृत ने चिक फ्रिंज लुक में डेब्यू किया

बॉलीवुड में फ्रिंज कट्स का ट्रेंड काफी चल रहा है, अनन्या पांडे, अदिति राव हैदरी और भूमि पेडनेकर जैसे एक्टर्स इस सीज़न में पहले से ही ऐसे ही लुक में दिख रहे हैं। हालांकि, निमृत का लुक सादगी और एलिगेंस के आसान मेल के लिए सबसे अलग है, जो उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट करता है। जबकि फैंस ने शुरू में अंदाज़ा लगाया कि यह ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल स्टाइल अपडेट है या किसी रोल से जुड़ा है, निमृत ने अब इस जिज्ञासा को शांत कर दिया है।

अपने नए लुक के बारे में बात करते हुए, निमृत ने शेयर किया, ÷मैंने असल में कुछ नया काम शुरू किया है, और यह लुक उसी प्रोजेक्ट के लिए है। मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहती थी, और फ्रिंज सही बदलाव लगा। एक नए नज़रिए के साथ एक नई जगह पर कदम रखना हमेशा रोमांचक होता है, और यह उस सफ़र का एक छोटा सा हिस्सा है।÷ एक्टर के एक करीबी सोर्स ने यह भी बताया, निमृत कुछ समय से अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थीं, और जब यह प्रोजेक्ट आया, तो यह सही समय लगा। फ्रिंज उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक नई लेयर जोड़ता है। निमृत रिलेटैबिलिटी और रीइन्वेंशन के बीच बैलेंस बनाए हुए हैं। इस नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और उनका लुक चर्चा में है, ऐसा लगता है कि एक्टर परफॉर्मेंस और प्रेजेंस दोनों के मामले में कुछ नया लाने के लिए तैयार हैं।

सलमान खान अनप्रोफेशनल हैं...,मातृभूमि से पहले भाईजान को लेकर चित्रांगदा सिंह से कही गई थीं ऐसी बातें

एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने रिवील किया कि सलमान खान का मातृभूमि के सेट पर कैसा रवैया था। फिल्मी गलियारों में सलमान खान की लेट-लतीफी के चर्चे कोई नए नहीं हैं। हमेशा से उन पर लेट आने के आरोप लगते आए हैं। हाल ही में, चित्रांगदा सिंह ने बताया कि मातृभूमि के सेट पर भी सलमान लेट आते थे या नहीं। चित्रांगदा सिंह पहली बार सलमान खान के साथ काम रही हैं। दोनों आगामी फिल्म मातृभूमि में नजर आने वाले हैं। एक हालिया इंटरव्यू में चित्रांगदा ने रिवील किया कि मातृभूमि में काम करने से पहले कई लोगों ने उन्हें सलमान के बारे में चेतावनी दी थी। साथ ही एक्ट्रेस ने अभिनेता के बारे में भी काफी अफवाहें सुनी थीं।

सलमान की लेट-लतीफी पर बोलीं चित्रांगदा

सलमान खान के बारे में चित्रांगदा सिंह ने बताया, फिल्म बहुत मेहनत और दिल से बनाई है। लोग सलमान के बारे में कहते हैं कि वे ऐसे हैं, वे वैसे हैं। यहां तक कि मुझे भी इस बारे में काफी टिप्स मिली थीं। जैसे कि मुझे हर समय तैयार रहना होगा क्योंकि वह टाइम पर नहीं आएंगे और शूटिंग का शेड्यूल भी लंबा खिंच सकता है।

अन प्रोफेशनल नहीं हैं सलमान खान

सलमान खान को लेकर यह भी अफवाहें उड़ती हैं कि वह सेट पर अनप्रोफेशनल हैं। हालांकि, चित्रांगदा ऐसा नहीं मानती हैं। एक्ट्रेस ने कहा, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई लोगों के मुंह से अफवाह सुनने के बाद मैं तैयार थी कि वह अनप्रोफेशनल हैं लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वह बहुत ही मिलनसार और सहज हैं।

खेल समाचार

15 साल के वैभव ने हर जगह दिल जीता

नई दिल्ली,27 अप्रैल 2026। आईपीएल के उन्नीसवें सीज़न में वीराकोट्टूडू से मुकाबला कर रहे वैभव सूर्यवंशी के खेल को हर कोई सलाम कर रहा है। वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को डॉट्स दिखा रहा यह लड़का जहाँ भी दिखता है, फैंस जमा होकर कहते हैं, सेल्फ़ी प्लीज़.. बस एक फ़ोटो। पंद्रह साल का वैभव अपनी उम्र के हिसाब से एक शरारत से सबको हैरान कर रहा है। इसी के तहत, इस बदमाश ने कहा कि जो भी उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने आएगा, उससे वह 100 रुपये लेगा। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी से एयरपोर्ट पर दो बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहा। इस पर उसने उनसे कहा, भाई, फ़ोटो के पैसे लूँगा। सच कह रहा हूँ। सौ रुपये लूँगा। जब उसने कहा कि वह ऐसे पैसे लेगा तो बच्चे चौंक गए। वे तुरंत अपने मम्मी-पापा के पास गए और 200 रुपये लेकर वैभव को देने वाले थे। हालांकि..उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए और उन्होंने उनका मज़ाक उड़ाने के लिए ऐसा कहा था। इसके बाद आईपीएल स्टार ने एक फोटो खिंचवाई और उन्हें खुश किया। राजस्थान मैनेजमेंट ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जिसने भी देखा, वह मज़ेदार कमेंट्स कर रहा है और कह रहा है, क्रिकेट में स्टार बन चुके वैभव की बचकानी हरकतें अभी भी बाकी हैं।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर थोमस कप क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

नई दिल्ली,27 अप्रैल 2026। थॉमस कप में भारतीय शटलरों ने प्रभावित किया। पुरुषों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी और डबल्स में सात्विक-चिराग की जोड़ी ने भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत दिलाने में मदद की। उन्होंने सोमवार को ग्रूप्र के दूसरे टाई मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 5-0 से हराया और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ग्रूप ए पॉइंट्स टेबल में अभी दूसरे नंबर पर मौजूद भारत अगले मैच में चीन का सामना करेगा। हाल ही में शानदार फॉर्म में चल रहे युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने श्रेय ढांड को सीधे सेटों में हराया। आयुष ने अपने विरोधी को डराते हुए 21-8, 21-6 से जीत हासिल की और भारत को बढ़त दिलाई। बाद में, डबल्स में सात्विक चिराग ने रिज़्की हिदायत और जैक यू को 21-14, 21-16 से हराया। प्रणय ने भी अपनी ताकत दिखाई और ऋषि होंडा भूपति को 21-11, 21-17 से हराया। पहले दो स्थानों पर चारों ग्रुप में से हर एक में टॉप दो टीमें थॉमस कप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो डेनमार्क में खेला जा रहा है।

रायपुर में 10 और 13 मई को आईपीएल मुकाबला

रायपुर ,27 अप्रैल 2026। आईपीएल 2026 राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु व्ही/एस मुंबई इंडियंस और 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु व्ही/एस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों मैच शाम 7ः30 बजे से शुरू होंगे।

इस आईपीएल मैचों को लेकर टिकट बुकिंग मई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है। हालांकि इस मामले में आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक आरसीबी की टीम 8 मई को रायपुर पहुंचेगी और यहां 6 दिन तक रहेगी। टीम मैदान पर प्रैक्टिस भी करेगी। मुंबई इंडियंस की टीम भी 8 मई के बाद राजधानी पहुंचने की संभावना है।

2 हजार का हो सकता सबसे सस्ता टिकट

टिकट आरसीबी की आधिकारिक वेबसाइट से ही ऑनलाइन बुक किए जाएंगे। सबसे सस्ती टिकट रूपए 2000 की होगी। इसके अलावा रूपए 2500, रूपए 3500,रूपए 5000 और रूपए8000 तक की कैटेगरी में होगी। इसके अलावा प्लैटिनम सीटों के सामने लगे कांच के पैनल हटा दिए गए हैं। अब दर्शक खिलाड़ियों को बिना किसी रुकावट के और करीब से देख सकेंगे।

पाकिस्तान ने की जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज़ के लिए 15-सदस्यीय टीम की घोषणा

नई दिल्ली,27 अप्रैल 2026। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ़ होने वाली तीन मैचों की ओडीआई सीरीज़ के लिए 15-सदस्यीय टीम की घोषणा की। यह सीरीज़ 4 मई से शुरू होगी और जून में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप से पहले, आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025-2029 की तैयारियों का हिस्सा है। आईसीसी के अनुसार, मोमिना रियासत को इस महत्वपूर्ण असाइनमेंट के लिए पहली बार ओडीआई टीम में शामिल किया गया है। टीम की कप्तानी फ़ातिमा सना करेंगी। उनका लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ हाल ही में हुई व्हाइट-बॉल सीरीज़ में मिली हार के बाद वापसी करना होगा; उस दौरे के दौरान पाकिस्तान ओडीआई और टी20 आई दोनों सीरीज़ 2-1 से हार गया था। पाकिस्तान इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ़ ओडीआई सीरीज़ में एक जीत दर्ज करने के बाद,आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025-2029 की पॉइंट्स टेबल में दो अंकों के साथ फिलहाल पाँचवें स्थान पर है। ज़िम्बाब्वे व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगा। टीम 29 अप्रैल को कराची पहुँचेगी और फिर 30 अप्रैल से 3 मई तक नेशनल बैंक स्टेडियम में अभ्यास करेगी। दूसरा और तीसरा ओडीआई क्रमशः 6 मई और 9 मई को खेला जाएगा, जिसके बाद 12 मई से तीन मैचों की टी20 आई सीरीज़ शुरू होगी। सभी मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएँगे।

फ़ातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज़, आयशा ज़फ़र, डायना बेग, गुल फिरोज़ा, मोमिना रियासत, मुनीबा अली ,नजीहा अल्वी (विकेटकीपर), नशरा संधू, नतालिया परवेज़, रमीन शमीम, सदाफ़ शमास, सिदरा अमीन, सैयदा अरूब शाह और तस्मिया रुबाब। पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे महिला व्हाइट-बॉल सीरीज़ का शेड्यूलः पहला ओडीआई- 3 मई दूसरा ओडीआई- 6 मई तीसरा ओडीआई - 9 मई पहला टी20 आई - 12 मई दूसरा टी 20 आई- 14 मई तीसरा टी 20 आई- 15 मई ।

अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए नई पार्टनरशिप का ऐलान

लॉस एंजिल्स,27 अप्रैल 2026। नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स,जो चार महाद्वीपों में क्रिकेट फ्रेंचाइजी के मालिक हैं और इस खेल के सबसे जाने-माने ग्लोबल ब्रांड्स में से एक हैं, ने लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के ऑफिशियल क्रिकेट डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर क्रिकमैक्स कनेक्ट के साथ पार्टनरशिप की है। एलएकेआर और क्रिकमैक्स कनेक्ट द्वारा आज अनाउंस की गई इस पार्टनरशिप से, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में यूथ क्रिकेट को डेवलप करने के लिए नाइट राइडर्स क्रिकेट एकेडमी का एक नेशनल नेटवर्क बनाया जाएगा। हालांकि मेजर लीग क्रिकेट के ज़रिए यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोफेशनल क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले ही डॉलर 300 मिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्ट किया जा चुका है, लेकिन रफ़्तार बढ़ती जा रही है। हाल ही में, लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स और फेयरप्लेक्स ने लॉस एंजिल्स के पोमोना में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड की नींव रखी, जो दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया का पहला डेडिकेटेड क्रिकेट वेन्यू और 2026 एमएलसी सीज़न के लिए एलएकेआर का ऑफिशियल होम ग्राउंड होगा। इस वेन्यू पर सात मैच होने हैं, जिसमें 1-5 जुलाई तक एलएकेआर के पहले तीन होम मैच शामिल हैं। इन डेवलपमेंट के साथ-साथ, ज़मीनी स्तर पर प्रोग्राम बनाना भी उतना ही ज़रूरी है जो अलग-अलग लीग के लिए एक फीडर सिस्टम बनाएं और युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए बढ़ावा दें। जैसे-जैसे क्रिकेट के लिए अमेरिकी दर्शक तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 5.4 मिलियन दक्षिण एशियाई डायस्पोरा और उससे आगे के लोगों में, यह पार्टनरशिप नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के दुनिया भर में साबित फ्रैंचाइज़ी मॉडल को क्रिकमैक्स कनेक्ट के कम्युनिटी क्रिकेट डेवलपमेंट में एक दशक पुराने ट्रैक रिकॉर्ड, एकेडमी और टाउनशिप पार्टनरशिप के इसके स्थापित नेटवर्क, और प्लेएलए ओलंपिक यूथ इनिशिएटिव के क्रिकेट पार्टनर के रूप में इसकी खास भूमिका के साथ जोड़कर उस अंतर को भरने के लिए डिज़ाइन की गई है।

भारतमाला परियोजना जमीन घोटाला...पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के भाई भूपेंद्र चंद्राकर के घर ईडी की दबिश

12 से ज्यादा अधिकारी खंगाल रहे दस्तावेज,अभनपुर में भी एक्शन

धमतरी,27 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सोमवार तड़के ईडी की टीम ने धमतरी के कुरूद में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर छापेमारी की। साथ ही कुरूद में ही राइस मिलर रौशन चंद्राकर के यहां रेड मारी गई। इसके अलवा अभनपुर में जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। यह कार्रवाई सुबह से जारी है। सुबह तीन गाड़ियों में 12 से अधिक ईडी के अधिकारी भूपेंद्र चंद्राकर के घर पहुंचे। टीम घर के अंदर जांच-पड़ताल कर रही है। आरोप है कि उन्होंने कथित भारतमाला घोटाले में अपने करीबियों को सिर्फ अभनपुर ही नहीं, बल्कि कायाबांधा (अभनपुर),दुर्ग,पाटन, राजनांदगांव के देवादा और मगरलोड जैसे क्षेत्रों में करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलवाया है। इन आरोपों से संबंधित शिकायत दस्तावेजों के साथ दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर ईडी यह जांच कर रही है।

जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं का खुलासा : शुरुआती जांच में सामने आया है कि कृषि भूमि को बैकडेट में गैर-कृषि घोषित कर उसका मुआवजा कई गुना बढ़ाया गया। साथ ही एक ही खसरे की जमीन को कागजों में अलग-अलग हिस्सों में बांटकर अलग-अलग लोगों के नाम पर भुगतान किया गया। ईडी इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति अटैच कर चुकी है।

घर अंदर से लॉक कर दस्तावेजों की जांच

धमतरी में कुरूद के सरोजिनी चौक के पास भूपेंद्र चंद्राकर का घर है, जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी की टीम घर के अंदर जांच कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षाबल भी मौजूद हैं। घर के अंदर से ताला लगाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर ना जा सके।

शिकायतों के आधार पर ईडी की जांच

रायपुर, अभनपुर में इससे पहले भी ईडी ने गोपाल गांधी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका जताई जा रही है।

अफसरों ने नहीं की पुष्टि : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। ईडी बीजेपी नेता के भाई और कुछ जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर जांच कर रही है, हालांकि पूरे मामले में अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं।

भारतमाला प्रोजेक्ट और वेदांता हादसे पर भी घेरा

भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई कार्रवाई पर बैज ने कहा,'देर आए दुरुस्त आए ', लेकिन इसमें बड़े नेताओं की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलहाल केवल छोटे मोहरों पर कार्रवाई हो रही है,जबकि बड़े जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईडी (ईडी) बड़े आरोपियों पर भी कार्रवाई करेगी? वहीं वेदांता हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? यह दबाव के बाद दर्ज की गई। उन्होंने दावा किया कि आज भी यह एफआईआर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है और अब तक जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने इसे 'लीपापोती' करार दिया।

ईवीएम में गड़बड़ी के दावों पर हाईकोर्ट सख्त सांसद भोजराज नाग को मिली बड़ी राहत

रायपुर,27 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यायधानी बिलासपुर से आ रही है। कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद भोजराज नाग की सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सांसद नाग को बड़ी राहत देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर की उस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है,जिसमें ईवीएम में छेड़छाड़ और काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। इस फैसले के बाद कांकेर से लेकर रायपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है।

ईवीएमऔर रैंडमाइजेशन पर उठाए थे सवाल

मामला कांकेर संसदीय सीट के चुनावी नतीजों से जुड़ा है। कांग्रेस के तत्कालीन उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर आरोप लगाया था कि 26 अप्रैल 2024 को हुए मतदान में इस्तेमाल हुई मशीनों बैलेट यूनिट,कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में गड़बड़ी की गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,याचिका में दावा किया गया था कि गुंडरदेही, सिहावा, संजरीबालोड, डोंडी लोहारा और केशकाल विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17ष्ट और रैंडमाइजेशन रिपोर्ट में मशीन नंबरों का मिलान नहीं हो रहा है।

सिर्फ शक से काम नहीं चलेगा,सबूत लाएं

जस्टिस की बेंच ने मामले की गंभीरता से सुनवाई की, लेकिन बीरेश ठाकुर की दलीलों को फिलहाल अपर्याप्त माना। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि मशीनों की दोबारा जांच या वेरिफिकेशन का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता,जब तक कि गड़बड़ी के पुख्ता मौखिक या दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड पर न हों। हाईकोर्ट ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया एक गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे केवल आशंकाओं के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

कांग्रेस प्रत्याशी के पास अब भी है एक मौका

भले ही कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन बीरेश ठाकुर के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। कोर्ट ने उन्हें यह छूट दी है कि यदि वे वोटों की गिनती में गड़बड़ी से जुड़े ठोस दस्तावेजी या मौखिक सबूत जुटा लेते हैं, तो वे दोबारा नई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यानी अब गेंद बीरेश ठाकुर के पाले में है कि वे आरोपों को साबित करने के लिए क्या नया रिकॉर्ड पेश करते हैं।

विशेष सत्र पर सियासत तेज : पीसीसी चीफ दीपक बैज का सरकार पर हमला

कहा...राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए बुलाया गया सत्र

रायपुर,27 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 30 अप्रैल को बुलाया गया विशेष सत्र राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और इसका मकसद कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना है। दीपक बैज ने कहा कि राज्यपाल की अधिसूचना में 'महत्वपूर्ण कार्य' का उल्लेख किया गया है,लेकिन महिला आरक्षण बिल 2023 पहले ही संसद से पारित होकर कानून बन चुका है। ऐसे में विधानसभा में इस पर चर्चा का क्या औचित्य है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह लोकसभा का अपमान नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार को सत्र बुलाना ही है, तो ढाई साल के अपने कार्यों पर चर्चा करे और 'मोदी की गारंटी' पर बहस कराए।

पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पर भी उठाए सवाल

पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर भी पीसीसी चीफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जहां-जहां यह व्यवस्था लागू हुई है, वहां यह असफल साबित हुई है। राजधानी में कानून-व्यवस्था सुधारने के बजाय सिर्फ वसूली हो रही है। जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन जैसे मामलों में बेवजह चालान काटे जा रहे हैं, जबकि लूट, हत्या और चोरी जैसी गंभीर घटनाओं पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस 'वसूली मास्टर' बन गई है।

बैज ने आरोप लगाया कि जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने के लिए यह विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भूपेश ने उठाए संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सवाल

रायपुर,27 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी के दावों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में न सिर्फ बीजेपी की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन,संसदीय परंपराओं और संवैधानिक दायरे को लेकर भी गंभीर मुद्दे खड़े किए। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इससे पहले भी ऐसे दावे किए गए थे और परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आए। उनका इशारा पिछले चुनावों की ओर था,जहां बीजेपी ने आक्रामक प्रचार के बावजूद अपेक्षित सफलता हासिल नहीं की थी। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा,बीजेपी की राजनीति अब केवल दावों और प्रचार तक सीमित रह गई है,जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। उनके अनुसार, जनता अब इन दावों को गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि बार-बार ऐसे दावे विफल साबित हुए हैं।

बीजेपी एसबीआई बन गई है : अपने बयान में बघेल ने कहा, पहले बीजेपी उन्हें और उनकी पार्टी को एटीएम कहती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद बीजेपी एसबीआई बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में बीजेपी मिलकर संसाधनों का दोहन कर रही है और विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बघेल के अनुसार, सरकारों का प्राथमिक उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है।

विधानसभा के विशेष सत्र पर सवाल

भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी कई संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सत्र बुलाने के लिए अनुमति ली गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि एजेंडा क्या है और किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए

क्या इस विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है? यदि लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित होता है, तो क्या उसका प्रभाव राज्य विधानसभा पर भी पड़ेगा? क्या यह स्थिति केंद्र और राज्य के बीच टकराव की ओर इशारा करती है या यह सहमति का मामला है? इन सवालों के जरिए बघेल ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच अधिकारों और सीमाओं को लेकर स्पष्टता आवश्यक है।

तीन बिल आए और तीनों गिर गए

बघेल ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार तीन महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई थी, लेकिन तीनों ही पारित नहीं हो सके। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन विधेयकों की विफलता पर विधानसभा में चर्चा होगी? उनके अनुसार, यह केवल विधायी प्रक्रिया की विफलता नहीं है, बल्कि सरकार की नीति और तैयारी पर भी सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर ये बिल क्यों गिर गए और इसके पीछे क्या कारण थे।

50 लाख की ठगी का खुलासा...ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड पुलिस ने महिला समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायपुर,27 अप्रैल 2026। राजधानी रायपुर में 50 लाख रुपये गबन मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी ड्राइवर कृष्णा साहू समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 49 लाख 50 हजार रुपये नकद, एमजी विंडसर कार (सीजे 04 क्यूजी 6633) और वारदात में इस्तेमाल वर्ना कार (सीजे 06 एचबी 8055) जब्त की गई है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 66.50 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड ड्राइवर कृष्णा साहू ही था, जिसने अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ मिलकर पहले से साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता अखिलेश ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे उनके जीजा उमेश अग्रवाल ने फोन कर बताया कि ड्राइवर कृष्णा साहू और अकाउंटेंट भूपेंद्र देवांगन कंपनी की कार से करीब 50 लाख रुपये लेकर बैंक गए थे, लेकिन बैंक बंद होने के कारण वे वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गीतांजलि नगर स्थित भारत माता मूर्ति के पास ड्राइवर ने गुटखा लेने के बहाने अकाउंटेंट को कार से उतार दिया और मौका पाते ही कार समेत 50 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। घटना के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर और पुलिस उपायुक्त (क्राइम) स्मृतिक राजनाला के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी विश्लेषण किया और आरोपी की मूवमेंट को ट्रैक किया। मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए लगातार दबिश दी गई, जिसके बाद आरोपी कृष्णा साहू को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूर्व मंत्री के बेटे ने की खुदकुशी,पारिवारिक कलह और पत्नी से विवाद बना मौत की वजह

रायपुर,27 अप्रैल 2026। राजधानी रायपुर के मोवा क्षेत्र में एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूर्व राज्य मंत्री (मध्यप्रदेश शासन) धनीराम साहू के 45 वर्षीय बेटे जय साहू ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना पंडरी थाना क्षेत्र की है।

बताया जा रहा है कि मृतक पिछले कुछ समय से गंभीर पारिवारिक तनाव से जूझ रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार, घटना बीती रात लगभग 9 बजे के आसपास की है। मृतक के बड़े भाई भागवत साहू ने पंडरी थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी कि जय साहू ने खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया है।

डीपीआई का आदेश : जिस स्कूल के लिए जारी हुआ पोस्टिंग आदेश,वहीं करनी होगी जॉइनिंग,सभी अभ्यावेदन खारिज

रायपुर,27 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर डीपीआई ने कड़ा आदेश जारी किया है। जिला और संभाग स्तर पर खारिज किए गए शिक्षकों के अभ्यावेदनों को डीपीआई ने खारिज कर दिया है। राज्य शासन ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया था। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की उपलब्धता को संतुलित करना और शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक तथा आवश्यकता वाले स्कूलों में पदस्थापन सुनिश्चित करना था। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग के माध्यम से 'अतिशेष' शिक्षकों को उन स्कूलों में पदस्थ किया गया, जहां शिक्षकों की कमी थी। हालांकि, इस प्रक्रिया से असंतुष्ट शिक्षकों ने अपने नए पदस्थापन को स्वीकार नहीं किया और विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए जिला एवं संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण समितियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। जिला और संभाग स्तर पर अभ्यावेदनों की विस्तृत जांच की गई। जांच के बाद पाया ,युक्तियुक्तकरण की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से की गई है। इसके आधार पर सभी अभ्यावेदनों को खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद,कुछ शिक्षकों ने संचालनालय स्तर पर फिर से अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। डीपीआई ने संचालनालय स्तर पर भी पूरे मामले की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान जिला और संभाग स्तर पर की गई कार्रवाई को सही पाया। लिहाजा, संचालनालय ने शिक्षकों के अभ्यावेदन को खारिज कर दिए। इस फैसले के बाद अब संबंधित शिक्षकों के लिए अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य हो गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यदि कोई शिक्षक आदेश के बावजूद जॉइनिंग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

इंसानियत शर्मसार: जिस पड़ोसी के भरोसे मां छोड़ गई थी बेटी,उसी ने मासूम को बनाया हवस का शिकार,पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

रायपुर,27 अप्रैल 2026। राजधानी रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खोलागांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 20 वर्षीय युवक ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली चार साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, घटना उस वक्त हुई जब मासूम की मां किसी काम से पोस्ट ऑफिस गई थी। बाहर तेज धूप होने के कारण मां ने सुरक्षा के लिहाज से अपनी बच्ची को भरोसेमंद समझकर पड़ोसी के घर छोड़ दिया था। इसी बीच, सूनेपन का फायदा उठाकर पड़ोसी युवक राहुल तारख (20 वर्ष) ने मासूम के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। अभनपुर थाना प्रभारी सत्येंद्र श्याम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि ग्राम खोलागांव से दुष्कर्म की सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई। उन्होंने बताया 'आरोपी राहुल तारख को गिरफ्तार कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ में फिर खुलेंगे शराब अहाते,'पहले आओ-पहले पाओ' नीति से होगा ऑनलाइन आवंटन

रायपुर,27 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब दुकानों के बाहर अहाते (बैठकर शराब पीने की व्यवस्था) शुरू होने जा रहे हैं। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए इनके आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अहातों का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इच्छुक आवेदक 20 मई से 15 मार्च 2027 तक कभी भी आवेदन कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट पर 24 घंटे आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी और सफल पंजीकरण के बाद आवेदकों को रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल और ईमेल पर भेजा जाएगा। प्रत्येक अहाते के लिए 5,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेस फीस तय की गई है, जबकि निविदा राशि का 5% अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा। चयनित होने पर यह राशि लाइसेंस फीस में समायोजित की जाएगी। आवेदकों के लिए सख्त शर्तें भी तय की गई हैं। केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आबकारी विभाग का बकाया नहीं है, वही आवेदन कर सकेंगे। साथ ही शराब निर्माण, परिवहन या थोक कारोबार से जुड़े लोग इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। जारी निर्देशों के अनुसार, लाइसेंस 1 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक मान्य होंगे। एक आवेदक एक जिले में अधिकतम दो अहातों का ही लाइसेंस ले सकेगा। लाइसेंस जारी करने का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को दिया गया है। चयनित आवेदकों को दो कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा, अन्यथा उनका चयन रद्द किया जा सकता है।

राज्यपाल डेका ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय की नई बस को दिखाई हरी झंडी...

रायपुर,27 अप्रैल 2026। राज्यपाल रमेन डेका ने लोकभवन में इंदिरा कला संगीत विश्व विद्यालय खैरागढ़ की नई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल छात्रों और स्टाफ के लिए परिवहन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस वाहन के माध्यम से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कला, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए विभिन्न स्थानों तक आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को अपने प्रतिभा प्रदर्शन के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। यह कदम विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन और छात्रों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है। राज्यपाल डेका ने वाहन के सदुपयोग, नियमित रखरखाव और विद्यार्थियों के हित में प्रभावी उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे संसाधन संस्थानों की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति देते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. लवली शर्मा सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)